● वर्ष-4
● अंक-05
रायपुर, बुधवार
14 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

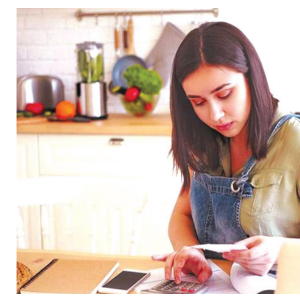

पेज-6›› फैमिली बजट प्लान करते समय इन...

कटघोरा में खुलेगी देश की पहली लीथियम खदान

नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए छग के स्वास्थ्य मंत्री

लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 2 हजार पीपीएम लीथियम कंटेन्ट की उपलब्धता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रीी विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6ठवीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खनिजों का दोहन और उनके उपयोग के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की भी चर्चा हुई। जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लीथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लीथियम एक अहम धातु है जिससे राज्य और देश विकास की नई दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि लीथियम खदान के शुरु हो जाने से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और विकसित भारत, 2047 के योगदान में छत्तीसगढ़ के लीथियम भंडार का बड़ा योगदान होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी जारी किया गया है। इन 20 ब्लॉक्स में से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लिथियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जीएसआई द्वारा प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2 हजार पीपीएम लिथियम कन्टेन्ट पाया गया है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्युटिकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि में होती है। इस खनिज के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।

भारत-बाग्लादेश सीमाः तीन दिन में 83 फ्लैग मीटिंग

कोलकाता। पड़ोसी मुल्क में जारी उथल-पुथल के बीच, गृह मंत्रालय के निर्देशों पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए शनिवार को सदस्यों की एक

बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा बीएसएफ के महानिदेशक के निर्देशों पर, समिति के सदस्यों ने अपने समकक्षों के साथ संवाद स्थापित किया। साथ ही, बीओपी-कंपनी स्तर तक समकक्षों तक पहुंचने के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 83 फ्लैग मीटिंग की गई है। इसके अलावा दोनों सीमा सुरक्षा बलों ने पूर्वी कमांड ज़िम्मेदारी के इलाके के संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में लगभग 241 समन्वित गश्त की हैं।

सीमा सुरक्षा बल (पूर्वी कमान), कोलकाता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बीएसएफ अधिकारियों ने बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर आने से रोकने में बीजीबी की भूमिका की सराहना की और भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) न केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑप्स मामलों में बीएसएफ के साथ सहयोग कर रहा है, बल्कि उनके नागरिक अधिकारियों के साथ मिलकर बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा के लिए भी सभी कदम उठा रहा है। हाल ही में, 9 अगस्त को, जब 1500 बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश के अंदर कूचबिहार-लालमोनिरहाट जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इकट्ठा हुए थे, तो बीजीबी ने बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें वापस लौटने के सफल प्रयास किए। इसके अलावा द्विपक्षीय क्षेत्रीय बैठकों में, सीमा सुरक्षा और अन्य आपसी हितों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।

बंगाल में अपने चरम पर अराजकता, कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं

नई दिल्ली। कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार-हत्याकांड मामले को लेकर देशभर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महिला डॉक्टर की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पीजी छात्रा के साथ जो घटना घटी है, वह वाकई दिल दहला देने वाली है और इसने पूरे विश्व और देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। राज्य की टीएमसी सरकार पर हमला करते हुए नड्डा ने कहा कि जिस तरह से यह घटना घटी और जिस तरह से सरकार ने इसे छिपाने की कोशिश की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, अराजकता अपने चरम पर है और दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और यह सब एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद हो रहा है, यह और भी अधिक चिंताजनक है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

नीतीश कुमार की खामोशी के राजनीतिक मायने

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल में देखें तो पूरी तरीके से चुप नजर आ रहे हैं। उनके सार्वजनिक कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में वह दो दिन पटना के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर थे जहां बाढ़ का पानी आया हुआ है। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बना रखी है। मीडिया में नीतीश कुमार का बड़ा बयान बजट के दिन आया था जब उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, उसमें भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा था। ऐसे में नीतीश कुमार की खामोशी कुछ ना कुछ संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश की खामोशी की असली वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक शायद नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। भले ही वह भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। लेकिन उन्होंने मुस्लिम वोटो की उम्मीद नहीं छोड़ी है। शायद इसी वजह से वह लगातार मुस्लिम वोटो को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर जो केंद्र सरकार द्वारा बिल लाया गया है, वह नीतीश को असहज कर रहा है। पार्टी के मुस्लिम नेता भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। भले ही गठबंधन धर्म को निभाते हुए संसद में जदयू के ललन सिंह ने इसके पक्ष में जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी। लेकिन कहीं ना कहीं जदयू इस बात पर अपनी खुशी दिख रही है कि यह मामला जेपीसी के पास चला गया। नीतीश कुमार को लगता है कि इस तरह के बिल की वजह से उनके अल्पसंख्यक वोट खिसक सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया है। इसके अलावा उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराकर उसी हिसाब से आरक्षण देने का भी काम किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण बढ़ाने का मामला अटक गया। ऐसे में नीतीश कुमार को इसका श्रेय नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर उन्हें समर्थन भी नहीं मिल रहा है। कोट में कोटा आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार शुरू से इसके बड़े पक्षधर रहे हैं। हालांकि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब दलित सब कोटा फैसले को लागू करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। शायद इस वजह से भी नीतीश बहुत खुश नहीं है।

प्रशांत किशोर का मामला भी नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रहा है। प्रशांत किशोर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तो हमलावर रहते ही हैं, नीतीश कुमार पर भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि, प्रशांत किशोर भाजपा पर उस तरीके से हमलावर नहीं दिख रहे हैं। आरजेडी तो लगातार प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता रही है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दो अतिरिक्त जजों को दिलाई शपथ

बिलासपुर। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में बिभु दत्त गुरू तथा अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अतिरिक्त जज के रूप में शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 12 अगस्त 2024 को उक्त नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी थी।

प्रमुख समाचार

विनेश फोगाटः अब 16 को आएगा फैसला

पेरिस। खेल पंचाट के तदर्थ प्रभाग ने मंगलवार को भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला फिर 16 अगस्त तक स्थगित कर दिया। खेल पंचाट को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाना था, लेकिन इसे फिर तीसरी बार टाल दिया गया। इससे 29 वर्षीय भारतीय पहलवान का इंतजार बढ़ गया है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की विज्ञप्ति के अनुसार, खेल पंचाट के तदर्थ प्रभाग के अध्यक्ष ने विनेश फोगाट बनाम यूनाईटेड विश्व कुश्ती (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मामले में एकमात्र मध्यस्थ डॉ. एनाबेले बेनेट को अपना फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार 16 अगस्त 2024 पेरिस समय के अनुसार शाम छह बजे तक अनुमति दी है। पिछले मंगलवार को जापान की युई सुसाकी के खिलाफ जीत सहित तीन जीत के साथ महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश को अंततः स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ खिताबी मुकाबले से बाहर कर दिया गया क्योंकि सुबह वजन करते समय उनका वजन निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया।

हिंसा करने वालों को सजा मिलेः हसीना

नई दिल्ली। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर फैली हिंसा को लेकर इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहला बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने देशवासियों से 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने की अपील की। वहीं हाल ही में जेल से रिहा हुईं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने बुधवार और गुरुवार को अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देने का एलान किया है। इस धरने के दौरान खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने की मांग करेंगीं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी मां का पहला बयान पोस्ट किया। उन्होंने कहा प्रिय देशवासियों, 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके प्रति गहरा सम्मान रखें।

ट्रम्प हो या कमला हर किसी के साथ काम करने को तैयार

नई दिल्ली। मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी पद पर हो। नई दिल्ली में इंडियास्पोरा की प्रभाव रिपोर्ट के लॉन्च पर आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बारे में बोलते हुए, जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी प्रणाली अपना फैसला सुनाएगी और भारत किसी भी सरकार के साथ काम करने की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त है। जयशंकर ने कहा कि आम तौर पर, हम दूसरे लोगों के चुनावों पर टिप्पणी नहीं करते क्योंकि हम यह भी आशा करते हैं कि दूसरे हम पर टिप्पणी न करें। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था अपना फैसला सुनायेगी. और, मैं इसे केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर आप पिछले 20 वर्षों पर नजर डालें, तो शायद हमारे लिए थोड़ा और, हमें पूरा विश्वास है कि हम यूनाइटेड के राष्ट्रपति के साथ काम करने में सक्षम होंगे। यह पूछे जाने पर कि वह वर्तमान वैश्विक स्थिति को कैसे देखते हैं, एस जयशंकर ने यूक्रेन और इज़राइल में चल रहे संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया एक असाधारण कठिन दौर का अनुभव कर रही है।

राज्य सरकार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करें

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार

को राज्य सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान के लिए अभियान शुरू करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदकों की भूमि दस्तावेजों और निवास स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाएं। पीठ ने कहा कि पड़ोसी देश से अवैध आव्रजन एक खतरनाक समस्या है और राज्य तथा केंद्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बहस के दौरान याचिकाकर्ता दानियाल दानिश ने अदालत को बताया कि संथाल परगना के छह जिलों - देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा में अवैध अप्रवासी बस गए हैं.

दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर फहराया गया 735 मीटर लंबा तिरंगा

जम्मू। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग-अलग जगहों पर समारोहों की तैयारी हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपने-अपने स्थानों पर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के रियासी में एक ऐसा ही बड़ा आयोजन हुआ, जहाँ लोगों, मुख्य रूप से छात्रों ने चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली। छात्रों ने अपने हाथों में तिरंगा थाम रखा था और अपने सिर के ऊपर वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति के नारे लगाए। पूरे मार्च के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों ने उन्हें घेर रखा था। देशभक्ति के एक भव्य प्रदर्शन में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा की सड़कों पर मंगलवार को 600 फुट लंबा तिरंगा लहराया गया। यह कार्यक्रम %हर घर तिरंगा% कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसे भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय स्कूलों के 2,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने तिरंगा पथ यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों पर चुप क्यों है भारत का विपक्ष

योगेंद्र योगी

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे हमलों पर भारत के विपक्षी दलों की खामोशी बताती है कि वोट बैंक की राजनीति किस हद तक हावी है। यदि ऐसे ही हमले भारत या किसी पड़ौसी देश में मुसलमानों पर हुए होते तो विपक्षी दल आसमान सिर पर उठा लेते। इजराइल के हमास आतंकियों के खिलाफ हमले में मारे गए मुसलमानों के मामले में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं के दिए गए बयान इसका प्रमाण हैं। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवडियों के रास्तें में दुकानदारों से नामों के खुलासो के निर्देश पर विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को खतरे में बताया था। विपक्षी दलों का कहना था कि इससे अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इधर जब मुसलमान बांग्लादेश में हिन्दुओं के घर-मंदिर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान जला रहे हैं, तब विपक्षी दलों को खास चिंता नहीं है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की हार के एक प्रमुख वजह यही दोमुंही नीति भी रही है।

बांग्लादेश में देश में 1 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूके। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को यहां निशाना बनाया जाता रहा है। बांग्लादेश में जारी अनिश्चितता और अराजकता के माहौल के बीच वहां के करीब 27 राज्यों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है।

हिन्दुओं पर इतना अत्याचार होने के बावजूद उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना तो दूर इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना तक नहीं की। इस आलोचना में भी विपक्षी दलों को मुस्लिम वोट बैंक खतरे में नजर आता है। साफ जाहिर है कटु आलोचना करने का मतलब है कट्टरपंथी मुसलमानों की आलोचना करना। विपक्षी दलों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अनिवार्य रूप से नेमप्लेट लगाने के फैसले पर विपक्षी दलों ने जमकर हायतौबा मचाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि जैसे दिया बुझने से पहले फडफ़ड़ाता है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फडफ़ड़ा रहा है इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। जेडीयू का कहना था कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट, दाल-चावल बन जाएगा? ठीक वैसे ही कोई अल्ताफ या रशीद आम-अमरूद बेच रहा है, वो गोश्त तो नहीं बन जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा था कि पश्चिमी उप्र व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा मार्ग में पडने् वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश एक गलत परम्परा है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। मुसलमानों के हर मुद्दे पर संविधान की दुहाई देने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे घोर अत्याचारों पर लचर बयान देकर इतिश्री कर ली। इसके विपरीत ओवैसी ने कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कटु आलोचना की थी। ओवैसी ने इसकी तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में हिटलर के तानाशाही फैसले से करते हुए कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडेनबॉयकॉट था।

हिन्दुओं के हितों के मुद्दों पर विपक्षी दलों का रवैया पूर्व में भी ऐसा ही रहा है। कनाडा में एडमोंटन शहर में स्थित बीएपीएस स्वामिनारायण मंदिर में तोडफ़ोड़ की गई और दीवार पर पेंट कर दिया गया। कनाडा में पहले भी हुए मंदिरों पर हमले होते रहे हैं। खालिस्तान समर्थक यहां अक्सर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं। अगस्त 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था और खालिस्तानी जनमत संग्रह का पोस्टर लगा दिया गया था। इसके अलावा भी ब्रिटेन, अमरीका सहित कई देशों में हिन्दुओं और उनके धार्मिक-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले होते रहे हैं। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने हिन्दु विरोधियों को कभी निशाने पर नहीं लिया। ऐसे मुद्दों पर विपक्षी नेताओं के बयान तक नजर नहीं आते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमरीका यात्रा के दौरान भाजपा के कारण भारत के संविधान को खतरे में बताया था। वही राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।

खास बात यह है कि बांग्लादेश में यह हालत तब है जबकि भारत ने कदम-कदम पर उसका साथ दिया है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का शिकार बांग्लादेशियों को आजादी दिलाई बल्कि बांग्लादेश को पैरों पर खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश भारत की बिजली और अन्य मदद पर निर्भर है। भारत का बांग्लादेश में अरबों का निवेश है। भारत के हाथ खींचने से बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं। बांग्लादेश पहले से ही चीन का कर्जदार है। चीन का कर्जा इतना बढ़ चुका है कि चीन अब बिना कुछ लिए मदद नहीं करने वाला है। ऐसे में कट्टरपंथियों के हिन्दुओं पर हमले से बांग्लादेश से भारत के संबंधों में खटास आना तय है। इसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा।

पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली समेत पांच माओवादी गिरफ्तार

■ विस्फोटक भी बरामद

सुकमा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुकमा जिले में लगातार पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर से सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां जगरगुण्डा थानाक्षेत्र से 01 महिला सहित 05 नक्सलियों को विस्फोटक सामाग्री के साथ सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार किया है। जिनमें से 01 गिरफ्तार नक्सली पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पद के अनुरुप 05 लाख रुपये का इनाम घोषित है। इनामी नक्सली गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) क्षेत्र में सक्रिय रहा है। सभी गिरफ्तार नक्सली थाना जगरगुण्डा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

मामले की पुष्टि करते हुए सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि नक्सलियों को गिरफ्तार करने में जिला बल, डीआरजी एवं 165 वाहिनी सीआरपीएफ की रही संयुक्त कार्यवाही। जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की आ-सूचना पर संयुक्त पार्टी नक्सल गस्त सर्चिंग हेतु ग्राम मिसीगुड़ा व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। तभी मिसीगुड़ा के जंगल-पहाड़ी चिकोमेट्टा के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे, जिन्हे घेराबंदी कर 05 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम क्रमशः 01.उईका चैतू पिता सुकलु (पूर्व एसीएम/परमिली एरिया कमेटी सदस्य, गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) ईनामी 05 लाख) उम्र- लगभग 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी पटेलपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, 02. कुंजाम सुखलाल पिता सोमालू (मिलिशिया सदस्य, इंद्रावती एरिया) उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी पाण्डूपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, 03. पदाम हुंगा पिता पदाम पण्डा (मिलिशिया सदस्य/जीआरडी कमांडर) उम्र लगभग 24 वर्ष जाति मुरिया निवासी पाण्डूपारा थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा, 04. महिला उईका लखे पिता उईका हुंगा (सीएनएम सदस्य, चिन्नागेलुर एरिया) उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी मिसीगुड़ा पटेलपारा, थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, 05. पदाम सन्नू पिता सोमालू (मिलिशिया सदस्य) उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी मिसीगुड़ा पाण्डूपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा का होना तथा नक्सल संगठन में उपरोक्त पदों पर कार्य करना बताया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों की चेकिंग करने से क्रमशः 01. उईका चैतू से गुलाबी रंग के पॉलिथीन में रखा हुआ 100 ग्राम बारुद, टाईगर बम 01 नग, डेटोनेटर 02 नग, माचिस 01 नग, 02. कुंजाम सुखलाल के कब्जे से हरे रंग के प्लास्टिक थैले में रखा हुआ बीजीएल सेल 01 नग, जिलेटीन रॉड 02 नग, कोर्डेक्स वॉयर 01 मीटर लगभग 03. पदाम हूंगा से हरे रंग के प्लास्टिक थैले में रखा हुआ बारुद 100 ग्राम, 02 नग डेटोनेटर, पेंसिल सेल 02 नग, नक्सल साहित्य, 04. उईका लखे से सफेद रंग के प्लास्टिक थैले में रखा हूआ 02 नग जिलेटिन रॉड, कोर्डेक्स वॉयर, टॉप टाइगर बम 01 नग, माचिस 01 नग, 05. पदाम सोमलु के कब्जे से प्लास्टिक थैले में में रखा हूआ जिलेटिन रॉड 02 नग, कोर्डेक्स वॉयर 01 नग, बिजली वॉयर 03 मीटर लगभग, पेंसिल सेल 01 नग बरामद किया गया। उपरोक्त सामाग्री को रखे जाने के संबंध में गहन पूछताछ करने पर बताये कि बड़े नक्सलियों के आदेश पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से रखना तथा मौके पाकर सुरक्षाबलों के आने-जाने वाले मार्ग में आईईडी लगाने के लिये आना बताये ।

उक्त कृत्य विधि विरूद्ध पाये जाने से उक्त नक्सलियों के खिलाफ थाना जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 18/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सभी नक्सलियों के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया । उपरोक्त घटना में शामिल अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया ऑपरेशन

रायपुर/धमतरी। गरियाबंद एवं धमतरी पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। माओवाद प्रभावित सुदूर अंचलों में गरियाबंद-धमतरी पुलिस बल एवं सीआरपीएफ ने व्यापक ऑपरेशन अभियान चलाया। इस दौरान ओडिशा स्टेट कमेटी के धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन के माओवादियों द्वारा लगाए गए कई डंप बरामद किया गया है। वहीं 38 लाख रुपए नगद एवं नक्सल सामग्री जब्त की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रायपुर रेंज के अंदरूनी क्षेत्रों में सतत् नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सूचना मिली कि प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय माओवादी इकाइयों ने व्यापारियों एवं अन्य लोगों से अवैध रूप से लेवी वसूल की है। इस धन के साथ अन्य माओवादी सामग्रियों को गरियाबंद एवं धमतरी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में छिपाया गया है। सूचना मिलने पर गरियाबंद-धमतरी पुलिस बल एवं सीआरपीएफ को विशेष सर्चिंग अभियान पर 10 अगस्त को रवाना किया गया था और यह ऑपरेशन 12 अगस्त को पूरा हुआ। सर्चिंग के दौरान इस बल ने धमतरी-गरियाबंद के सीमा पर छोटे गोबरा एवं पेंड्रा के जंगल क्षेत्रों में जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी एवं झाड़ियों से छिपाकर लगाए गए डम्प में माओवादी सामग्री बरामद की गई। इसमें विभिन्न स्थलों से स्टील डिब्बे के अंदर 2000 नोट के 06 बंडल, 500 नोट के 52 बंडल प्रत्येक बंडल में 100 नोट कुल 38 लाख रुपए बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 23 नग बीजीएल के राउंड,दो नग टिफिन आईईडी, आईईडी बनाने से संबंधित सामग्री 13 नग डेटोनेटर, 01 बंडल फ्यूज वायर, 2 किलो लूज बारूद, यूरिया, 2 नग फ्लैस लाइट, 03 नग मल्टी मीटर, सेंसर रिमोट, इलेक्ट्रिक वायर, माओवादी वर्दी, काला कपड़ा एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इस संबंध में थाना मैनपुर में धारा 308 बीएनएस, धारा 17, 20, 21, 40 विविक्रि अधि. तथा थाना मेचका में धारा 109, 191 (2), 191 (3),190 बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट, 4, 5 विपअ तथा 10 विविक्रि, 13 (क), 16 (क) 38 (2), 39 (2) में अपराध दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस नेता गीदम जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पर हमला

■ आदिवासी समाज ने एनएच 63 पर लगाया जाम

दंतेवाड़ा। जिले के कांग्रेस नेता और गीदम जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम हपका पर धारदार हथियार से हमला कर कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर भी तोडफ़ोड़ की घटना को अंजाम देने की रिपोर्ट सर्व आदिवासी समाज ने गीदम थाने में दर्ज करवाई है। इसे लेकर आदिवासी समाज ने एनएच -63 पर करीब 4 घंटे जाम लगाकर प्रर्दशन किया। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में सोमवार शाम करीब 7 बजे से जगदलपुर-बीजापुर एनएच -63 पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके चलते जगदलपुर और रायपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें, ट्रक समेत अन्य वाहनों की कतार लग गई। पुलिस-प्रशासन के समझाने पर रात करीब 11 बजे जाम खोला गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि सुबह से फिर जाम लगाएंगे और नगर बंद रखेंगे।

जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम हपका ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे साथियों के साथ कुछ युवकों का विवाद हुआ था, मैं वहां पहुंचा था। 11 अगस्त की शाम एक युवक मेरे घर आया और चाकू दिखाया। उसने मुझे कहा कि आपके साथ मेरा कुछ नहीं है। फिर उसी दिन रात 10 बजे मुझे किसी माध्यम से बस स्टैंड बुलाया गया। जब मैं गीदम के बस स्टैंड पहुंचा तो वहां खड़े कुछ युवकों ने मुझ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकला। मेरे साथ मेरे दो साथी और थे। उन पर भी हमला किया गया, आज मेरे घर में घुस गए, घर में गाडियों में तोडफ़ोड़ की गई है। हपका ने कहा कि उन्हें जातिगत गालियां दी गई है, इस मामले को लेकर अब आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है।

सर्व आदिवासी समाज के गीदम ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र वेट्टी ने कहा कि जिसने हमला किया है वो तड़ीपार व्यक्ति है, उसने मनीराम पर हमला किया। अपने साथियों से भी हमला करवाया। उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी जो भी हो, लेकिन उन्होंने समाज को गालियां दी हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस से मांग है की कार्रवाई करे। हमारी मांग है कि जब तक आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ लेती। वह व्यक्ति हमारे पास आकर समाज से माफी नहीं मांग लेता, तब तक सड़क पर बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन हमें जवाब दे किआखिर तड़ीपार व्यक्ति नगर में घूम रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दंतेवाड़ा के डीएसपी नसरउल्ला सिद्दीकी ने बताया कि यह दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला है। उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमी को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र

बेमेतरा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमी को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट मिला है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य केन्द्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के उपलब्धि प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई देते हुए लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता डॉ. अंजू गोपे प्रधान एवं डॉ. सुधीर कुमार डहरिया द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र का दिनांक 03.05.2024 एवं 04.05.2024 को मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमी को 93.69 प्रतिशत स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट प्रदाय किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत कुमार ध्रुव ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये स्वास्थ्य सेवाओं के 6 अलग-अलग मानकों (व्क्कएएप्क्कएळम्छम्त ।स् ।क्डप्छौप्ज्त ।ज्प्व्छए स्।ठव्न्त् त्व्डए स्।ठए छ।ज्प्व्छ।स् भ्।स्ज्भ् च्व्ळ।ड्म्) के आधार पर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पाए जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टीम में उत्साह का संचार हुआ है और क्षेत्र की जनता को इसी प्रकार निरंतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित हुए ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमी को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट मिलने पर संस्था प्रभारी श्री चिंताराम साहू ने खुशी जाहिर करने हुए बताया कि यह सब अस्पताल में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (आरएमए श्री सुमित मिश्रा, नेत्र सहायक अधिकारी मुकेश टंडन, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती हुलसी शर्मा, स्टाफ नर्स श्रीमती महेत्रीन विन्ध्य राज, श्रीमती पदमनी वर्मा, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक श्रीमती गगन साहू श्रीमती हेमेश्वरी वर्मा, मनोज राजपूत, अनुज यदु, सुखनाथ कुमार, श्रीमती मधुलता, फार्मासिस्ट कु. प्रतिमा जोशी, लैब टेक्नीशियन कु दुर्गा टोन्ड्रे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती हीना वर्मा जेएसए रवेश कुमार साहू, सहायक ग्रेड 03 श्रीमती गीता गहरवार, आयुष्मान ऑपरेटर राधेश्याम साहू एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कु पूजा निषाद, श्रीमती सुशीला यादव, रिंकु साहू) के अपने कार्य के प्रति लगन का परिणाम है।

आखिर क्यों नहीं हो रही है जर्जर स्कूल की मरम्मत

क्लास रूम में छज्जा गिरने से शिक्षक समेत आधा दर्जन छात्राएं घायल

जांजगीर-चांपा। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और छत गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच आज जांजगीर-चांपा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां सरकारी स्कूल के कमरे का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे कई छात्र-छात्राएं और शिक्षक घायल हो गए हैं। घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के पुटपुरा गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हर दिन की तरह आज भी क्लास चल रहा था। इस दौरान दोपहर करीब 1:30 बजे जब कक्षा 6वीं के छात्र कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। जिसकी चपेट में आने से छात्र-छात्राएं और शिक्षक घायल हो गए। हादसे में 4 छात्रा, एक छात्र और एक शिक्षक घायल हुए है। हादसे के बाद सभी घायलों को आननफानन में जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया।

छज्जा गिरने से 4 छात्राएं और शिक्षक घायल

घायलों में कक्षा 6 वीं के छात्र समर राठौर (11 वर्ष), पूनम राठौर (11 वर्ष), मानवी यादव (11 वर्ष), राधिका केवट (12 वर्ष), शिक्षा यादव (11 वर्ष) और एक शिक्षक शामिल हैं। छात्रा शिक्षा यादव के सिर और पैर में ज्यादा चोट आई है, लेकिन वह खतरे से बाहर है।

कमरे में पानी टपकने की दो दिन पहले ही दी गई थी सूचना

इस स्कूल भवन का निर्माण 1999 में हुआ था, और हाल ही में इसके एक कमरे में पानी टपकने की समस्या आई थी। इस समस्या के बारे में सरपंच को दो दिन पहले ही सूचित किया गया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज यह हादसा हुआ। गनीमत रही की सभी बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन प्रशासन की ठिलता से आज बड़ा हादसा हो सकता था। यह घटना सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति और रखरखाव में कमी को उजागर करती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मुंद्रिका सिंह बने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष

बलरामपुर रामानुजगंज । बलरामपुर रामानुजगंज सनवाल क्षेत्र के प्रखर आदिवासी युवा नेता जनपद सदस्य मुंद्रिका सिंह को जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर के द्वारा शासकीय महाविद्यालय रामचंद्रपुर का जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ग्राम इंद्रवतीपुर के रहने वाले मुद्रिका सिंह शुरू से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनकी सक्रियता को देखते हुए भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सनवाल बनवाया गया था। वहीं भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महामंत्री फिर कार्यवाहक अध्यक्ष का भी दायित्व संभाल चुके है। संगठन के प्रति निष्ठा एवं समर्पण को देखते हुए उन्हें भाजपा का मंडल अध्यक्ष एवं वर्तमान में भाजपा का जिला मंत्री बनाया गया है। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम का आभार माना। जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में सबसे कम उम्र (21 वर्ष) में सरपंच बनने का मुद्रिका सिंह का रिकॉर्ड है। बहुत कम उम्र से राजनीति की शुरुआत की थी।

तीन शातिर ठग एटीएम कार्ड बदलकर करते ठगी, गिरफ्तार

बालोद। कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड को बदलकर लाखों की ठगी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से 142 नग एटीएम कार्ड, पांच मोबाइल, एक स्वाइप मशीन सहित 25 हजार रुपये नगदी रकम बरामद की है। तीनों आरोपी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। दरअसल, तीनों आरोपी लोगों की मदद करने के बहाने से एटीएम कार्ड को बदलकर अपने पास रख लेते थे और दूसरे एटीएम कार्ड को थमा देते थे। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने कहा लोगों के एटीएम कार्ड को अपने पास रखकर उसमें से पैसे निकाल लेते थे। तीनों आरोपी बालोद सहित कवर्धा, सुकमा राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, दुर्ग बेमेतरा सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे।

पार्षद के घर में खेला जा रहा था जुआ, छह जुआरी पकड़ाया

राजनांदगांव। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी के पास पार्षद के घर पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पार्षद राजेश उर्फ चम्पू गुप्ता और एक अन्य आरोपी फरार, जुआ के फाड़ से 10 लाख 5 हजार 500 रुपए नगद सहित तास की पत्ती जप्त,बसंतपुर पुलिस ने घर में की छापामार कार्रवाई। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्षद के घर में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रहे थे जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बसंतपुर थाना पुलिस ने कोतवाली थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी कार्रवाई की। वार्ड नंबर 41 के पार्षद राजेश गुप्ता के घर जुआ खेला जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बसंतपुर पुलिस ने निर्दलीय पार्षद के घर दबिश दी। पुलिस ने 10 लाख 5 हजार 500 रुपये सहित तास की पत्ती की बरामद की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पार्षद राजेश गुप्ता और एक अन्य आरोपी फरार है।

बोलेरो हादसे का शिकार पुलिस कर्मी समेत दो घायल

कोरबा। मानिकपुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक और दो अन्य लोग गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए। जहां तीनों घायल हो गए। इस हादसे में एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। मानिकपुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक नन्हे सिंह, चालक अनिल यादव और एक अन्य साथी किसी काम से सोमवार की रात पाली चैतमा की ओर गए हुए थे। इस दौरान तड़के सुबह वापस लौटते समय पाली चैतमा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गए। जहां तीनों घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक अनियंत्रित होने के कारण बोलेरो वाहन सड़क पर पलट गई और सभी घायल हो गए। चालक अनिल यादव के सर और हाथ में गंभीर चोटे आए हैं। हादसे के बाद देखते ही देखते लोगों के भीड़ एकत्रित हो गई और घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां जांच के दौरान अनिल यादव को बिलासपुर रेफर किया गया।

भिलाई ननि के तीन कांग्रेस पार्षदों ने दिया इस्तीफा!

भिलाई। भिलाई नगर निगम के तीन पार्षदों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तीनों ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इधर, कांग्रेस अध्यक्ष समेत इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। मतलब इस्तीफे की खबर तो है,पर पुष्टि न तो पार्षद कर रहे हैं और न ही अध्यक्ष। उधर समर्थक बता रहे हैं कि सभी ने आरोप लगाया है कि पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी इसलिए वे आहत थे, अगला कदम क्या होगा अभी तय नहीं है। भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल ने कहा है मैंने भी दूसरों से सुना है। मेरे पास इस्तीफे की पुख्ता जानकारी नहीं हैं। बता दें कि वार्ड तीन के पार्षद हरिओम तिवारी, वार्ड नौ की पार्षद रानू साहू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वार्ड छह के पार्षद रविशंकर कुर्रे ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। ननि में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दोनों निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस को समर्थन देते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

रिश्वतखोर बाबू को एसीबी ने किया गिरफ्तार

■ एरियर की राशि निकालने चपरासी से मांगी थी घूस

बलरामपुर। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों सहायक ग्रेड 2 के बाबू को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफनगर में की है। इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग के एक चपरासी नितेश रंजन पटेल से एरियर की राशि रिलीज़ करने के नाम पर सहायक ग्रेड 2 के बाबू गौतम सिंह ने 20 हजार रुपये की मांग की थी। वहीं आज नितेश पटेल रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 12 हजार रुपये देने के लिए बीईओ ऑफिस गया था, लेकिन इससे पहले ही एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर गौतम सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया।

प्रार्थी ग्राम पंचायत ओदारी निवासी नितेश रंजन पटेल ने बताया कि वह मिडिल स्कूल चलगली में पीयून के पद पर पदस्थ है। वह एरियर की राशि रिलीज़ कराने के लिए गया था। जहां बाबू गौतम सिंह ने एरियस निकलवाने के एवज में 20 हजार रिश्वत की मांग की। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने सरगुजा एसीबी कोटीम से की। जिसके बाद प्लानिंग करके एसीबी की टीम ने जल बनाकर रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों पकड़ा । फिलहाल गौतम सिंह को हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का हुआ अंतिम रिहर्सल, उपमुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि

जगदलपुर। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों के लिए अंतिम रिहर्सल मंगलवार सुबह लालबाग मैदान में किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में अपर कलेक्टर सीपी बघेल रहे, उन्होंने परेड की सलामी ली। साथ में कलेक्टर विजय दयाराम, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने भी परेड की सलामी ली।

कलेक्टर श्री विजय ने तैयारियों का जायजा लेकर समय पर सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस परेड का नेतृत्व डीएसपी दीपमाला कुर्रे, सेकंड कमांड डोमेन्द्र सिन्हा कर रहें है। परेड में 15 टुकडियां शामिल हो रही है जिसमें सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन, सीआरपीएफ 80 बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, 19वीं पोखरण वाहिनी, जिला बल पुलिस, वन विभाग, नगर सेना, जिला बल, एनसीसी और स्काउट गाइड के जवान है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा होंगे। रिहर्सल में स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, आयुक्त नगर निगम हरेश मंडावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल योगेश देवांगन, एसडीएम भरत कौशिक सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मंत्री राम विचार नेताम

■ दो किलोमीटर तक चले पैदल

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामनुजगंज जिला मुख्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कृषि मंत्री राम विचार नेताम,भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल के उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाला गया। नेताम हाथ में तिरंगा लिए 2 किलोमीटर से अधिक पैदल तिरंगा यात्रा में चले इस दौरान भारत माता जय के जमकर जयकारे लगाए गए।

कृषि मंत्री राम विचार नेता ने कहा कि तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर गर्व की अनुभूति हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान में आप सब शामिल होकर गर्व से आजादी का पर्व मनाए उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य है कि सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा कर आजादी का जश्न मनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देशवासी इस अभियान में देशभक्ति के भावना के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। यह राष्ट्रव्यापी अभियान लोगों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उद्देश्य देश भक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान हर एक भारतीय को गर्व की अनुभूति दिला रहा है। भारत का हर एक नागरिक इस अभियान में सम्मिलित हो रहा है। हाई स्कूल मैदान से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई जो कलेक्टर बंगला होते राम विचार नेताम के सहयोग कार्यालय तक जाकर समाप्त हुई।

संक्षिप्त समाचार

15 अगस्त को रहेगा प्रदेश में मांस - मटन विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

रायपुर। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गुरूवार को मांस - मटन का विक्रय पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2024 गुरूवार को नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2024 गुरूवार को किसी भी दुकान में मांस - मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस - मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 15 अगस्त 2024 गुरूवार को नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने -अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस - मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

स्वतंत्रता दिवस पर वन मंत्री कश्यप दुर्ग में करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रदेश के संसदीय कार्य ,वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे तथा मुख्यमंत्री का संदेश वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री राजवाड़े बलरामपुर में करेंगी ध्वजारोहण

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रदेश की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर में ध्वजारोहण करेंगी तथा मुख्यमंत्री का संदेश वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा।

आईएएस चंदन कुमार बने वित्त विभाग में विशेष सचिव

रायपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चंदन कुमार को वित्त विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वित्त विभाग के आदेशानुसार चंदन कुमार द्वारा विशेष सचिव (बजट) का कार्य किया जाएगा।

रायपुर रेंज आईजी ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को किया इधर से उधर

रायपुर। रायपुर रेंज के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। जिसमें सहायक उप निरीक्षक (एएसआई), प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। यह ट्रांसफर आदेश आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने जारी की है। जारी आदेश के अनुसार, रायपुर रेंज के रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के कुल 84 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है। इनमें 14 एएसआई, 22 प्रधान आरक्षक और 48 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है।

सड़कें कुछ माह में ही उखड़ी, उद्योग मंत्री ने कार्रवाई करने कमिश्नर को लिखा पत्र

रायपुर। शहर की आधा दर्जन सड़कों के डामरीकरण के कुछ महीने में ही उखड़ जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी को वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने गंभीरता से लेते हुए कोरबा निगम आयुक्त को सड़क की जल्द मरम्मत करने और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने पत्र लिखा है। मंत्री श्री देवांगन ने आयुक्त को लिखे पत्र में उल्लेख किया है की कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत कोसाबाड़ी, सीएसईबी चौक से बुधवारी, वीआईपी मार्ग, निहारिका मार्ग पर 8 महीने पहले ही डामरीकरण निगम द्वारा कराया गया था। गुणवत्ताहीन एवम् भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण उक्त मार्ग डामरीकृत गिट्टी उखड़ गई है, इससे धूल उडने् के कारण आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने सड़क मरम्मत की नितांत आवश्यकता को देखते हुए जल्द सड़क मरम्मत प्रारंभ करने कहा है।

छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का दावा, कहा- जल्द होंगे नक्सलमुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को खत्म करने गंभीरता से योजना बनाकर काम कर रही है। लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। आने वाले दिनों में देश पूरी तरह से नक्सलमुक्त, आतंकवाद और अलगाववाद मुक्त होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा- कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार ये कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने ईवीएम, चुनाव की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर प्रश्न खड़ा किया। ये केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ये किसी ना किसी षड़यंत्र का हिस्सा है।

'कोलकाता की निर्भया' को न्याय दिलाने प्रदेश के डॉक्टर्स हुए एकजुट

काली पट्टी लगाकर कर रहे मरीजों का इलाज, आज रखेंगे ओपीडी बंद, चालू रहेगी इमरजेंसी

रायपुर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की छात्रा से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या से केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश में गुस्सा है। इसकी बानगी रायपुर में भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सभी ओपीडी डॉक्टर मंगलवार को जहां काली पट्टी बांधकर मरीजों को अटेंड कर रहे हैं, वहीं बुधवार को विरोध-प्रदर्शन करेंगे।

यूडीएफए और छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक में फैसला 14 अगस्त को सामूहिक हड़ताल पर जाते हुए ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया गया। हड़ताल के दौरान इलेक्टिव सर्विसेज जहां बंद रहेंगे, वहीं इमरजेंसी सर्विस चालू रहेगी। बैठक में रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के जेडीए के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। बैठक में केंद्र सरकार से सीबीआई जांच सहित पांच सूत्रीय माँग रखी गई। इसके साथ राज्य सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।

डॉक्टरों की मांगों का जिक्र करते हुए एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुई घटना के आरोपियों को सीबीआई जांच के माध्यम से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। इसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान संरक्षण अधिनियम- स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्यस्थल पर हिंसा को रोकने के लिए पूरे भारत में जल्द से जल्द केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और

स्वास्थ्य प्रतिष्ठान संरक्षण अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।

पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यस्थल सुरक्षा प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गार्ड अपने ड्यूटी घंटों के दौरान अपने स्थान पर रहें और उनके काम की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। इसके साथ राज्य के भीतर मेडिकल कॉलेज परिसरों के भीतर अंधेरे क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अंधेरे स्थलों में उचित रोशनी लगाई जानी चाहिए, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज परिसरों के चारों ओर उचित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये कैमरे काम करने की स्थिति में हों।

छत्तीसगढ़ में ही नहीं घटना के केंद्र कोलकाता में भी डॉक्टरों का गुस्सा उबल रहा है। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (सीएनएमसी) के छात्रों ने ममता सरकार की लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई के विरोध में संदीप घोष के प्रवेश को रोकने के लिए गेट बंद कर दिया है।

दरअसल, जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को लेकर छात्रों के साथ आम लोगों के गुस्से को देखते हुए आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ममता सरकार ने चार घंटे बाद ही उन्हें सीएनएमसी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। ममता सरकार के कदम के विरोध में सीएनएमसी के छात्रों ने संदीप घोष को पदभार ग्रहण करने से रोकने के लिए कॉलेज गेट बंद कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने रेप के बाद पीड़िता का गला घोंटा। आरोपी ने पीड़िता का गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या की। रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 3 से 5 बजे के बीच डॉक्टर की हत्या की गई। पीड़िता के शरीर पर कई जगहों पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं।

आज देशभर में मनाई जाएगी विभीषिका दिवस

विभाजन के तथ्यों से आमजन होंगे रू-ब-रू

रायपुर। 14 अगस्त को देश के विभाजन की विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान विभाजन के तथ्य से जनता को रू-ब-रू कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में देश के विभाजन से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा विधायक राजेश मूणत ने दी।

तिरंगा यात्रा पर प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए विधायक राजेश मूणत ने बताया कि पश्चिम विधानसभा में तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी। 14 अगस्त को दोपहर 3 बजे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से यात्रा निकलेगी। आजादी के महापर्व में उत्सव के साथ मनाया जाएगा। दोपहर 4 बजे राम नगर से डेढ़ किलोमीटर का झंडा लेकर यात्रा निकलेगी। बच्चों को वेशभूषा पहनाकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। भारत माता चौक में यात्रा संपन्न होगी।

विधायक मूणत ने बताया कि भारत माता चौक में आरती का कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सांसद रमेश बैस, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित विधायक मौजूद रहेंगे। भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे।

ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने सौंपा वित्तमंत्री चौधरी को ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल ने ओ.पी. चैधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से मिलकर ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने ज्ञापन सौंपा।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने ओ.पी. चौधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री को ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित बढ़ती जटिलताओं की जानकारी दी। वर्तमान में प्राप्त छूट हटने के कारण प्रतिदिन ई-वे बिल की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण जीएसटी विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा साथ ही साथ इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उदेश्य को क्षति भी हो रही है। साथ ही छोटे व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पारवानी ने ओ.पी. चौधरी से निवेदन किया कि दिनाँक 24 मई 2024 को जारी अधिसूचना पर पुन विचार करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना को यथावत रखा जाए। जिस पर मंत्री चौधरी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए चेंबर को आश्वस्त किया कि उपरोक्त प्रावधान से संबधित ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं होगी जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार सुरिन्दर सिंह, परमानंद जैन, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष भरत जैन एवं प्रीतपाल सिंह बग्गा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

डीएमएफ घोटाले पर महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी

- 1 करोड़ से अधिक की रकम की फ्रीज

रायपुर। पीएमएलए के तहत डीएमएफ (जिला खनिज निधि) घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चार स्थानों पर छापेमारी की। दो दिन पूर्व हुई इस कार्रवाई में 1.11 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। वहीं 76 लाख रुपए नगद बरामद किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में बताया कि डीएमएफ खननकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित एक ट्रस्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। राज्य सरकार के अफसरों और राजनीतिक अधिकारियों की मिलीभगत से डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने से पैसे निकालने में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई है।

ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अफसरों और राजनीतिक अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध परितोषण का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 25 फीसदी से 40 फीसदी तक है। रिश्वत के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी विक्रेताओं द्वारा आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। प्रवेश प्रदाताओं और उनके संरक्षकों की तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न आपत्तिजनक विवरण, कई फर्जी स्वामित्व इकाई और भारी नकदी मिली।

तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप 76.50 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। प्रवेश प्रदाता फर्मों से संबंधित 8 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इनमें लगभग 35 लाख रुपए डमी फर्मों से संबंधित विभिन्न टिकटें और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।

कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ

- 17 अगस्त को होगा महाविद्यालय और सीट का आबंटन

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बी.एस.सी. कृषि (ऑनर्स) स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काऊंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिनांक 09 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट 222.द्बद्दद्म1.ड्डष्.द्बठ्ठ पर आवेदन कर सकते हैं। काऊंसलिंग में शामिल होने के लिए दिशा-निर्देश एवं समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने हेतु 09 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 के मध्य ऑनलाइन पंजीयन करना एवं दस्तावेज अपलोड करना होगा। 16 अगस्त, 2024 को ऐसे अभ्यर्थी पुनः आवेदन कर सकते हैं जिनकी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के दौरान असफल लेनदेन हुई हो। 17 अगस्त, 2024 को पी.ए.टी.-2024 की प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को 20 से 23 अगस्त, 2024 के मध्य दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय, रायपुर में प्रातः 09:00 से सायं 5:30 बजे तक उपस्थित होना होगा। आबंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु अभ्यर्थियों को 20 से 24 अगस्त, 2024 के मध्य ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

सीट आबंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई सीट आबंटित नहीं हुई है, उन्हें भी स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग के लिए 20 से 25 अगस्त, 2024 (रात्रि 11:30 बजे) के मध्य ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि अभ्यर्थी सीट सुरक्षित करने के पश्चात सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो इस हेतु 20 से 25 अगस्त, 2024 (रात्रि 11:30 बजे) के मध्य सीट निरस्त करना होगा। आबंटित एवं रिक्त सीटों की जानकारी 27 अगस्त, 2024 को उपलब्ध कराई जाएगी।

अवैध भंडारण करने पर दाल मिलर के विरुद्ध कार्रवाई

पौने दो करोड़ का दाल जब्त, जमाखोरी का मामला दर्ज

रायपुर। दाल की बढ़ रही कीमतों का असर लोगों को परोसी जाने वाली थाली में पड़ रहा है। दाल बढ़ती कमीतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने थोक दुकान एवं दाल मिलों में जमाखोरी की जांच शुरू कर दी है।

खाद्य विभाग की टीम द्वारा दाल मिल का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दोंदेकला स्थित सदगुरु उद्योग की आकस्मिक निरीक्षण में 1,187.54 क्विंटल दाल जमाखोरी करते पाया गया। इस दाल का बाजार मूल्य 1 करोड़ 78 लाख 13 हजार रुपये बताई जा रही है। जांच में पहुंचे अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन में 1408.30 क्विंटल दाल पाया गया। जबकि दाल मिलर द्वारा स्टॉक की घोषणा केंद्र सरकार के पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री 220.76 क्विंटल की गई थी। ऑनलाइन एंट्री में अंतर मिलना खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

मामले में दाल जब्त कर 21 अगस्त तक मिलर को नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। दाल की जमाखोरी की रोकथाम करने और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए दालों का थोक व्यापारी 200 मीट्रिक टन तक दालों का भंडारण कर सकते हैं। थोक व्यापारी एक समय में एक प्रकार की दाल का 100 मीट्रिक टन से अधिक भंडारण नहीं कर सकता है। फुटकर विक्रेताओं के लिए नियम है कि पांच मीट्रिक टन दालों का भंडारण कर सकते हैं। मिलर्स की स्टॉक की सीमा पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 फीसदी होगी। खाद्य विभाग के नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा, दाल की जमाखोरी को रोकने के लिए थोक और फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ मिलर्स के पास दालों के भंडारण की समय सीमा तय कर दी है। दालों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण की रोकथाम के लिए टीमें जांच कर रही हैं।

रेलमंत्री से श्यामबिहारी की मांग, प्रदेश में दो ट्रेनों का हो विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की है। श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ की जनसुविधाओं से जुड़ी मांगों पर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री को चिरमिरी नागपुर हाल्ट नवीन रेल लाइन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली राज्यांश की राशि देने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने रेल लाइन विस्तार का काम जल्द से जल्द शुरु करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया है।

कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बिलासपुर-चिरमिरी-बिलासपुर ट्रेन नंबर 18257-18258 का विस्तार करने का प्रस्ताव रेल मंत्री के सामने रखा है। श्यामबिहारी की माने तो इस ट्रेन का विस्तार दुर्ग या गोंदिया जंक्शन तक होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में नवगठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लोगों को राजधानी रायपुर तक आने जाने के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है। इसलिए यदि बिलासपुर चिरमिरी ट्रेन का विस्तार दुर्ग या गोंदिया तक हो जाए तो सिर्फ राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि नागपुर तक आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी।

इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने शहडोल-नागपुर-शहडोल ट्रेन नंबर 11201-11202 को चिरमिरी से संचालित किए जाने की मांग की है। इससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को कटनी,जबलपुर और नागपुर से सीधे आवागमन की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त किया है की सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेज के लिए फंड, जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत चार मेडिकल कॉलेज के लिए 60 फीसदी केंद्र का अंश देने की मांग रखी। बता दें साय सरकार ने दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा और मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति बजट में दी है।

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से रायपुर में रीजनल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरएलटीआरआई) का अपग्रेड, क्षेत्रीय सिकल सेल उपचार और पुनर्वास केंद्र (आरएसटीआरसी) के रूप में करने की मांग की है, ताकि राज्य में सिकिल सेल से प्रभावित मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके।

जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मनेंद्रगढ़ के लिए साल 2015 में 45 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत टर्शरी कैंसर अनुसंधान संस्थान केंद्र की जल्द से जल्द स्थापना करने की भी मांग रखी। इसकी स्थापना से प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के कैंसर पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए इसे भारत सरकार के उपक्रम एसईसीएल के अस्पतालों में योजना के तहत इलाज की सुविधा देने की भी मांग केंद्रीय मंत्री से की। मंत्री जायसवाल की मांगों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विचार करने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ में शुरू होगी देश की पहली लिथियम माइंस : मंत्री श्यामबिहारी

साय सरकार छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के कटघोरा में जल्द लिथियम की माइंस शुरू करने जा रही है। यह देश की पहली लिथियम की माइंस होगी। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कटघोरा में लिथियम का भंडार है। यह माइंस लगभग ढाई सौ हेक्टेयर में होगी। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्री श्यामबिहारी ने बताया, विश्व में लिथियम का भंडार बहुत सीमित है। भारत में छत्तीसगढ़ के अलावा जम्मू कश्मीर में ही लिथियम का भंडार मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लिथियम की संभावना है, यहां भी जल्द सर्वे शुरू होगा। कोलकाता में हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ओपीडी डॉक्टर आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, यह घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है। धरती के भगवान और सेवा करने वाले डॉक्टर के साथ ऐसी घटना बंगाल में हुई, यह शर्मनाक कृत्य है। आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है , सरकार पूरी तरह से गंभीर है। बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें सुरक्षा के लिए हमारी पूरी तरह से व्यवस्थाएं है। हम सुरक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त करेंगे।

चीन पर काबू रखना जरूरी

केएस तोमर

ढाका में शेख हसीना शासन के पतन और उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए चीन का मुकाबला करने के लिए भारत एवं अमेरिका को एक संयुक्त रणनीति बनाने की सख्त जरूरत है, जिसने पहले ही अपनी विस्तारवादी नीति के जरिये हमारे अधिकांश पड़ोसियों को फंसा लिया है और बांग्लादेश उस सूची में शामिल होने वाला एक नया नाम है। विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि पारस्परिक हित और बाध्यता के सिद्धांत के कारण भारत और अमेरिका को बांग्लादेश के प्रति अपनी मौजूदा नीति में बदलाव लाना होगा, जो चीन और पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और जिससे दक्षिण एशिया में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आरोप लगा रही हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने में अमेरिका का हाथ रहा है। लेकिन भारत बांग्लादेश की नई सरकार से अलग-थलग नहीं रह सकता है, जिसका नेतृत्व वही खालिदा जिया कर सकती हैं, जो खुद को भारत-विरोधी खेमे का मानती हैं। ढाका की नई सरकार पर खालिदा जिया और कट्टरपंथी हावी हो सकते हैं, जिससे भारत के लिए सिरदर्द पैदा हो सकता है। अमेरिका को हसीना शासन के निष्कासन से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चीन मजबूत होगा, जो महाशक्ति देश के रूप में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। इसलिए अमेरिका को भारत की मदद से चीन का मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि भारत विश्व मंच पर आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। साथ ही भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखनी होगी, जिसने पहले ही मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका तक को अपने पाले में मिला लिया है। बांग्लादेश भी उसके पिछलग्गू बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने पड़ोसी पहले की नीति में भू-राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तनाव पैदा किया है और भारत को कमजोर करने के लिए भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। लेकिन कई क्षेत्रों में अमेरिका की करीबी देखते हुए उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो पारस्परिक विश्वास और लाभ के सिद्धांत पर आधारित होगा। आलोचकों का मानना है कि भारत को अपनी विदेश नीति में भारी बदलाव लाने की जरूरत है, अन्यथा चीन हावी हो सकता है, जो बीआरआई के जरिये हरेक देश में भारत विरोधी ताकतों की मदद करता है, जैसा कि बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के साथ ही काम करने में विश्वास करता रहा और संभावित विपक्ष खालिदा की बीएनपी को नजर अंदाज करता रहा। अब हसीना विरोधी ताकतें ढाका में सत्ता में आई हैं, जो भारत को दुश्मन समझती हैं। अगर भारत ने बीएनपी के साथ अच्छे संबंध बनाए होते, तो पाकिस्तान की आईएसआई और चीन पर अंकुश लगाया जा सकता था। भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत चल रही थी, क्योंकि यह दोनों देशों के व्यापार के लिए जरूरी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 के दौरान 13 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में एफटीए का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि ढाका की नई सरकार एफटीए चर्चा को बीच में ही छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे दोनों देशों के लोगों के हितों को नुकसान होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि यह समझौता जरूर होगा। राजनीतिक संकट के कारण लगभग 30 करोड़ डॉलर का निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है, खासकर तब, जब भारत हर दिन बांग्लादेश को तीन करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करता है। भारत का आयात जारी है, लेकिन निर्यात रुका हुआ है, जिसका समाधान अंतरिम सरकार को करना होगा, ताकि हर दिन बढ़ने वाले घाटे को रोका जा सके। बांग्लादेश हर दिन करीब 15 ट्रक मछली निर्यात करता था, जो अब घटकर एक ट्रक रह गया है। बांग्लादेश के कस्टम विभाग ने सैकड़ों भारतीय ट्रकों को बांग्लादेश में घुसने की मंजूरी नहीं दी है, जो पार्किंग में खड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम सरकार के नए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भारत विरोधी अभियान के जरिये सत्ता में आए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज्जू के शासन में मालदीव का झुकाव चीन की तरफ हो गया है।

मालदीव-भारत के बेहतर होते रिश्तों के सबब

ललित गर्ग

चीन की कटपुतली बने मालदीव को आखिर भारत की कीमत समझ में आ गयी। चीन एवं पाकिस्तान की कुचालों एवं षडयंत्रों से भारत के पडोसी देशों की हालात जर्जर होती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश है। लेकिन एक पडोसी देश के रूप में पिछले करीब एक साल की अवधि में मालदीव ने भी गहरे हिचकोले खाने एवं कई कड़वे अनुभवों से गुजरने के बाद अब पटरी पर आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पिछले सप्ताह हुई मालदीव यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का जैसा दोस्ताना रवैया देखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ आगे बढ़ने की मंशा जाहिर की, यह उन्हें अपनी गलती का अहसास कराने का ही द्योतक कहा जा सकता है। देर आये दुरस्त आये वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भारत-मालदीव के रिश्तों को भावनात्मक राजनीति के तकाजों पर कूटनीति की ठोस हकीकतों की जीत के रूप में देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पूर्व कार्यकाल में पडोसी देशों की यात्रा करते हुए उनसे भारत के संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं विकासमूलक बनाने के प्रयास किये। इसी के तहत मोदी की तत्कालीन मालदीव दौरे का मुख्य उद्देश्य नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सुरक्षा, विकास की दृष्टि के भारत के संबंधों को और मजबूत करना था। दौरे के दौरान मोदी को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान 'निशान इजुद्दीन' से भी सम्मानित किया गया। दरअसल मालदीव की दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर में जो स्ट्रेटजिक (सामरिक) लोकेशन है, वह भारत के लिए बेहद अहम है। मालदीव में पिछले कुछ सालों में चीन ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया है, उसे हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर उल्लेखनीय सफलता भी मिली। लेकिन यह सब करने के पीछे चीन का मुख्य लक्ष्य मालदीव की भारत से दूरी बढ़ाना भी रहा, जिसमें उसे बड़ी सफलता मिली। इस प्रकरण की शुरुआत पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर मुइज्जू ने भारत विरोधी भावनाओं पर दांव लगाया था। वह बार-बार सार्वजनिक तौर पर यह संकल्प

करते देखे गए कि सत्ता में पहुंचते ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से विदा कर देंगे। हालांकि सबको पता था कि भारतीय सैनिकों की वहां मौजूदगी सांकेतिक ही थी। भारत और मालदीव के बीच सदियों पुराने प्रेम एवं सौहार्द के रिश्ते एकाएक तल्ख होते दिखाई देने लगा। मालदीव की तरफ से लगातार तनाव बढ़ाने वाले बयान आते रहे, लेकिन भारत की तरफ से फिर भी संतुलित नीति अपनाई जाती रही है। इसी दौरान मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की, जिसका उद्देश्य कत्तई किसी भी देश के पर्यटन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने देश में पर्यटन की नई संभावनाओं को तलाशना है।

प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकाट मालदीव ट्रेंड होने लगा। इस हैशटैग के साथ लोगों के ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिसमें वे मालदीप और लक्षद्वीप की तुलना करते हुए लक्षद्वीप को बेहतर बता रहे है। मुइज्जू के भारत विरोध उनके अनेक मंत्रियों की तल्ख टिप्पणियों एवं रवैये के कारण वहां की अर्थ-व्यवस्था गिरने लगी, विशेषत: पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मालदीव की नई सरकार के रुख को देखते हुए भारत ने भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार कर ली। नतीजा यह हुआ कि भारत से छुट्टियां बिताने मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या कम होने लगी। इस साल के शुरुआती चार महीनों की अवधि में वहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 42 प्रतिशत घट गयी। ध्यान रहे, मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 30 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से चलने वाले इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रॉजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटका दिखाई देने लगा। मुइज्जू सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। किसी अन्य देश का सहयोग भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। ऐसे में मुइज्जू सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने रुख में बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया था। भारत ने भी इन संकेतों का सम्मान किया। नतीजा यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की यात्रा की, जिसके कारण दो पड़ोसी देशों के पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लौटते दिख रहे हैं।

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, लेकिन इन स्थितियों के कारण हुए भारी नुकसान का झेलते हुए मालदीव चीन के मनसूबों का भाप गया। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। यहां की नई सरकार चीन के करीब दिख रही है और चीन अपने मनसूंबो को पूरा करने के लिये गलत रास्तों पर ढकेल रहा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही 'इंडिया आउट' का नारा दिया था। भारत एवं मालदीव के बीच तल्खी अगर बढ़ती तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।

चीन हमारे रिश्तों की तल्खी का फायदा उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है। जिसका भारत ने खयाल रखा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से संतुलित नीति पर बल दिया जाता रहा है, जबकि मालदीव की तरफ से तो लगातार काफी कुछ गलत कहा जाता रहा है। लेकिन मालदीव को भी यह समझ आ गया कि भारत से दूरी उसके लिये नुकसानदायी है। चीन की तुलना में भारत से मालदीव के हित ज्यादा गहराई से जुड़े हैं। फिर भी मुइज्जू भारत के साथ रिश्तों में आ रही संभावित दूरी की भरपाई चीन से करीबी रिश्तों के रूप में करना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स तब भी इस बात की ओर ध्यान खींच रहे थे कि भू-राजनीति की वास्तविकताओं के मद्देनजर यह संभव नहीं है कि मालदीव में जो भूमिका भारत निभा सकता है, वह चीन निभाने लगे। फिर भी चीन की शह पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश होती रही है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद मुइज्जू के बयानों में हलकी सी नरमी जरूर दिखी, लेकिन नीतियों की दिशा बदलने का प्रयास फिर भी जारी रहा। लेकिन इससे हो रहे नुकसान को लेकर मुइज्जू सरकार सतर्क हो गयी। पर्यटन ही मालदीव की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत से करीब दो लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमिशन के आंकड़ों को मानें तो साल 2022 में 2 लाख 41 हजार और 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में भारत-मालदीव के बीच बढ़ रही दूरी का असर मालदीव के टूरिज्म एवं आर्थिक व्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक था।

भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा रहा हैं लेकिन चीन पोषित भारत विरोध की ऐसी अकारण नफरत भारत क्यों बर्दाश्त करें? निश्चित ही मालदीव के रवैये का दोनों देशों के बीच की सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव पडा। भारतीय यदि मालदीव का बहिष्कार करने लगा तो वहां अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी, यह बात समझने में मालदीव को देर नहीं लगी। अपनी भूल को सुधारते हुए उसने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जो दोनों देशों के हित में है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने में भारत सक्षम है, पडोसी देशों में भारत ही मजबूत स्थिति में है, आर्थिक एवं सामरिक दोनों ही दृष्टि से भारत अपने पडोसी देशों में सशक्त एवं ताकतवर है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अविशिष्ट-क्रम (भाग-7)

गतांक से आगे...

यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्म्यं कथयामास कूर्म्मरूपी जनार्दनः ।। इन्द्रद्युम्नप्रसङ्ग न ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ ।

अष्टादशसहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुषंगिकम् ।।

अर्थात्- जिस ग्रन्थ में लक्ष्मी कल्प को लक्ष्य करके इन्द्रद्युम्न के प्रसङ्ग द्वारा रसातल में कूर्मरूपी भगवान् ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का ऋषियों के प्रति निरूपण किया हो वह कूर्म पुराण है। जिसकी पद्यसंख्या अठारह हजार है।

इस समय उक्त पुराण की केवल एक संहिता ही प्राप्त है, शेष तीन संहिताएँ नहीं मिलतीं, अत: उपर्युक्त लक्षण भी अपनी सीमा तक घटित होता है। नारद पुराण में उक्त पुराण का प्रमाण 17 हजार लिखा है। कई पण्डितों के मत से वास्तविक प्रमाण 17600 है, जो 600 को अपेक्षाकृत एक हजार मानने पर या छोड़ देने हर उभयथा समन्वित हो जाता है। मुद्रित ब्राह्मी-संहिता कूर्मपुराण की पद्यसंख्या छः हजार है, जो नारद पुराण की सूची के अनुसार ठीक ही है।

ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्याब्रनोत्पुनः । तच्च द्वादशसाहस्र ं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम् ।।

अर्थात्- ब्रह्मा जी ने ब्रह्माण्ड का माहात्म्य दर्शाते हुये जिसका कथन किया हो वही ब्रह्माण्ड पुराण है। इसकी पद्यसंख्या बारह हजार दो सौ है । उपलब्ध ब्रह्माण्ड पुराण में उक्त लक्षण सर्वथा घटित होता है, प्रमाण भी पूरा उतरता है, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित इस पुराण का मूल नाम वायु पुराण छपा है, जिसका विवेचन यथास्थान किया गया है। पाश्चात्य समालोचकों ने भी उक्त पुराण की वास्तविकता को माना है।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है! एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए। घर-बार छूटा। परिवार छूटा। लाखों की जानें गईं। यह दर्द था, विभाजन का। भारत के लिए यह विभीषिका से कम नहीं थी। इसी दर्द को याद करते हुए आजादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। ऐलान, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का।

भारत का विभाजन देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं थी। इसका दर्द आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने पाकिस्तान को 1947 में भारत के विभाजन के बाद एक मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी

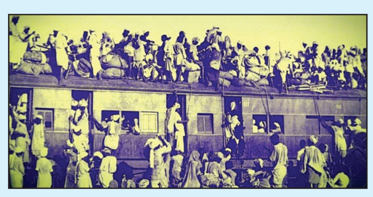

थी। लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के चलते कई लाख लोगों की जान चली गई थी।

इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए भी लाखों भारतीयों ने कुर्बानियां दी थीं। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आजादी के साथ देश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कहीं नामो-निशान नहीं था। अंग्रेज जा तो रहे थे, लेकिन उनकी साजिश का फलाफल था कि भारत को बांटकर एक अन्य देश खड़ा किया गया।

विभाजन की घटना को याद किया जाए तो 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए इतिहास का एक गहरा जख्म है। वह जख्म तो आज तक ताजा है और भरा नहीं है। यह वो तारीख है, जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। बंटवारे की शर्त पर ही भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली।

भारत-पाक विभाजन ने भारतीय उप महाद्वीप के दो टुकड़े कर दिए। दोनों तरफ पाकिस्तान (पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान) और बीच में भारत। इस बंटवारे से बंगाल भी प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा भारत का रह गया और बाकी पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। देश का बंटवारा हुआ लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं। इस ऐतिहासिक तारीख ने कई खूनी मंजर देखे। भारत का विभाजन खूनी घटनाक्रम का एक दस्तावेज बन गया जिसे हमेशा उलटना-पलटना पड़ता है। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खिंचते ही रातों-रात अपने ही देश में लाखों लोग बेगाने और बेघर हो गए। धर्म-मजहब के आधार पर न चाहते हुए भी लाखों लोग इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए।

इस अदला-बदली में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए। जो लोग बच गए, उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत-पाक विभाजन की यह घटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। यह केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। बंटवारे का यह दर्द गाहे-बगाहे हरा होता रहता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी दर्द को याद करने का दिन है।

बांग्लादेशी हिंदुओं के सड़कों पर एकजुट प्रतिरोध के मायने

अजय बोकिल

पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बीच वहां के मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों, उनके धर्मस्थलों को जलाने तथा कई हिंदू नेताओं की हत्या की घटनाएं हुईं। हालांकि बाद वहां के हिंदुओं ने जिस हिम्मत और धार्मिक प्रतिबद्धता के साथ राजधानी ढाका और कई शहरों में प्रदर्शन किया और अपने मानवाधिकारों की रक्षा की गुहार करते हुए अपनी मांगें नई सरकार के सामने रखीं, उसे नई वैश्विक हिंदू चेतना के आलोक में देखा जाना चाहिए।

दरअसल, इन साहसपूर्ण प्रदर्शनों का असर यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय सहित दुनिया के कई शहरों में हिंदू सड़कों पर उतरे और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक मांग की। दुनियाभर में संदेश गया कि हिंदू भी उतने ही पीड़ित हैं जितने कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय। इस वैश्विक दबाव का थोड़ा तो असर हुआ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं की रक्षा का वचन दिया। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बांग्लादेश के अंतरिम के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस को शपथ ग्रहण पर बधाई संदेश में वहां के हिंदुओं की रक्षा करने की अपील की थी।

बांग्लादेशी हिंदुओं का इस तरह सड़क पर आकर अपनी बात को दमदारी से रखना इसलिए भी अभूतपूर्व है, क्योंकि हिंदुओं ने सदियों से अपने धर्म और दर्शन का तो प्रसार किया, अपवाद

स्वरूप सैन्य विजय भी की, लेकिन कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एक साथ आवाज बुलंद की हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। जबकि दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ दुनिया के किसी कोने में भी होने वाली किसी भी ज्यादती के खिलाफ तमाम देशों में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। वैश्विक भाईचारा जागने लगता है। लेकिन इस तरह जागतिक भाई चारे की गरज शायद हिंदुओं ने कभी महसूस ही नहीं की या फिर ऐसी वैश्विक एकता का अंतरराष्ट्रीय राजनीति, आर्थिकी और सामाजिकी के संदर्भ में महत्व नहीं समझा। अगर समझा भी तो कभी उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की। व्यक्तिगत मोक्ष की कामना ही हिंदुओं का अंतिम साध्य रहा है। इसी तरह जगत कल्याण की उदात्त आकांक्षा के चलते वह अपने ही अधिकारों की सामूहिक रक्षा के आग्रह में मुश्किल से ही बदल पाता है।

हिंदू धर्म की ताकतवर सहिष्णुता का शायद सबसे कमजोर पक्ष यही है कि 'जियो और जीने दो' के आग्रह में हम यह भी भूल जाते हैं कि यह थ्योरी तभी सार्थक है कि जब दूसरा भी ऐसा चाहे। मूलतः यह सिद्धांत अति उदात्त भाव से प्रेरित होने के बाद भी एक ही हाथ से ताली बजाने की वकालत ज्यादा करता है।

बहरहाल, मुद्दा बांग्लादेश में हालात और धार्मिक विद्वेष के मारे हिंदुओं का है। विडंबना यह है कि सीधे धार्मिक टकराव में तो हिंदू निशाने पर होते ही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की लड़ाई का भी वो पहला शिकार होते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके दो बड़े उदाहरण हैं। 1971 में जब बांग्लादेश के मुस्लिम बंगालियों ने पाकिस्तानी फौज के दमन के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ी, उसमें भी बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याएं हुईं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। जबकि उनका सत्ता की लड़ाई से कोई सीधा सरोकार न था।

तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में बुरे हालात से जो 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए, उनमें ज्यादातर हिंदू ही थे, जिनमें से कम ही वापस बांग्लादेश लौटे। उसके बाद बांग्लादेश बनने के बाद भी टुकड़ों में हिंदुओं का भारत आना जारी है। फर्क इतना रहा कि जिस शेख हसीना सरकार को आज बांग्लादेश में फासिस्ट और अत्याचारी सरकार करार दिया जा रहा है, उसने काफी हद तक मुस्लिम कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई हुई थी।

इसी तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों के जबरन धर्मांतरण, धर्मस्थलों पर हमले, मूर्तियां तोड़ने और हिंदुओं को काफिर कहकर और नफरत बढ़ाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन हालात में कुछ हिंदू भारत भी आ जाते हैं। लेकिन सब भारत आ जाएं, यह व्यावहारिक भी नहीं है। इस दृष्टि से बांग्लादेशी हिंदुओं का बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरना वहां के नए सत्ताधीशों और कट्टरपंथियों के लिए भी चौंकाने वाला है। अमूमन घबराकर घर बार छोड़कर जाने वाली कौम अचानक पूरी ताकत से सड़कों पर कैसे उतर आई? क्योंकि आमतौर पर हिंदुओं से इस तरह के विरोध प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती। वो इकट्ठे भी होते हैं तो किन्हीं धार्मिक समागमों में। यह मान्यता आम है कि जिस तरह हिंदू सामाजिक रूप से एक नहीं होते, उसी तरह अपने व्यापक हितों और अस्मिता को लेकर कभी एक नहीं हो सकते।

जातीय विभाजन उन्हें एक ईकाई की तरह कभी एक नहीं होने देगा। वो मार खाते रहेंगे और कराहते रहेंगे और मुश्किल में भगवान से रक्षा की गुहार लगाते रहेंगे। इसके विपरीत बांग्लादेश में उभरा यह एकजुट विरोध भी हिंदुओं को वास्तव में कितना एक रखेगा, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस प्रतिरोध में वैश्विक हिंदू एकता का दिशादर्शक तत्व निहित हो सकता है। और यह एक अच्छा लक्षण है।

हिंदुओं के इस साहस को भारत में राजनीतिक हिंदुत्व की सीमित परिभाषा से आगे जाकर समझना होगा। क्योंकि विश्वभर में हिंदू धर्म न केवल सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है बल्कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म भी है। यह केवल एक किताब, एक अवतार, एक विचार से प्रसूत धर्म भी नहीं है। यह एक अनूठी जीवन शैली है, जो अपनी तमाम खामियों के बाद भी दुनिया में शाश्वत और नित्य नूतन है। इसे किसी विचार, अस्त्र, विष अथवा क्रूरता से नहीं मारा जा सकता। हिंदू धर्म अपने ही दम पर टिका है।

अपने ढीले-ढाले संगठन, असंख्य मत मतांतरों, दर्शनों और आराधना पद्धतियों के बाद भी जिंदा है। यह इसलिए भी अहम है कि आज जग में भारत और नेपाल जहां हिंदू बहुल है, वही करीब दो दर्जन देशों में हिंदू आबादी उल्लेखनीय संख्या में है। इसके बाद भी हिंदुओं की आवाज विश्व स्तर पर उतनी दमदारी से क्यों नहीं उभरती, उसे उस रूप में क्यों नहीं सुना जाता? क्या इसलिए कि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, जबकि इतर मान्यताओं में परिवार ही समूचे विश्व पर अपना हक जताते हैं?

यहां बात केवल किसी देश या राज्य में सत्ता हथियाने तक सीमित नहीं है बल्कि अपने वजूद और सम्मानपूर्वक जीने के हक को जताने की है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ दुनिया के कई देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में भी हिंदू अपने दायरों से बाहर निकल कर समर्थन में उतरे हैं तो यह वैश्विक हिंदू चेतना के जाग्रत होने का शुभ लक्षण है। कुछ जगह उनके समर्थन में ईसाई और यहूदी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया।

यहां भारत में भी आरंभिक राजनीतिक गुणा-भाग के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सधी हुई जबान में विरोध दर्ज कराना शुरू किया है। यह कैसे हो सकता है कि आप एक समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ राजनीतिक रूप से मुखर हों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय पर ज्यादती को भारत के आईने में देखकर अपनी भाव मुद्रा तय करें?

आज का इतिहास

1893 फ्रांस मोटर वाहन पंजीकरण शुरू किया गया जिसमे एक ड्राइविंग परीक्षण भी शामिल था।
1904 इस्माइल मोंटेस बोलीविया साउथ अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
1908 इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गयी।
1917 चीन गणराज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हंगरी में युद्ध करने की घोषणा की।
1917 चीन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1920 बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों की शुरूआत हुई।
1934 लड़ाकू क्रॉस की स्थापना न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में गई।
1941 युद्धपोतों पर एक गुप्त बैठक के बाद, ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन . रूजवेल्ट (सस्पेक्टेड) ने अटलांटिक चार्टर जारी किया, इस तथ्य के बावजूद कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध शुरू कर दिया था।
1942 बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राद पर हमला किया, और जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटिश जहाजों के साथ तीन दिवसीय लड़ाई लड़ रही थीं। अंग्रेजों ने कहा कि उनके विमान वाहक, ईगल को नष्ट कर दिया गया था।
1966 यू.एस. लूनर ऑर्बिटर को चंद्रमा के परिदृश्य की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था ताकि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र परिदृश्य पर उतरने के लिए तैयार किया जा सके।
1975 फिल्म द रॉकी हॉरर पिक्चर शो, जो आज भी रिलीज़ किया गया है, यह लॉस एंजेलिस में सबसे लंबे समय तक चलने वाली थिएट्रिकल रिलीज़ फिल्म का इतिहास है।
1979 फास्टनेट रेस के दौरान 15 नाविकों की मौत हुई।
1979 सात हवाओं के साथ एक भयंकर तूफान ने फास्टनेट दौड़ को 150 से अधिक नौकाओं के साथ अभी भी लापता होने और कम से कम 3 की मौत की सूचना दी है।
1980 डांस्क शिपयार्ड में लेच वाल्सा और उनके सहयोगियों ने हड़तालें शुरू कीं, जिसके बाद पोलैंड में सॉलिडैरिटीओवमेंट की स्थापना हुई।
1994 अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े कार्लोस द जैकल, यूरोप में एक नंबरऑफ आतंकवादी हमलों के लिए चाहते थे, फ्रांसीसी एजेंटों बायसुदानी अधिकारियों को सौंप दिया गया था।
2006 संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान वारबेटन लेबनान और इज़राइल में युद्ध विराम का उल्लंघन किया।

भारतीय उपमहाद्वीप में कब तक थमेंगी सांप्रदायिक व जातीय हिंसा

कमलेश पांडे

कहते हैं न कि नीतियां जब नरम होती हैं, तो अराजक तत्व हावी हो जाते हैं। राजतंत्र के कब्र पर पनपा समकालीन लोकतंत्र इसका जीता-जागता उदाहरण है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुई हिन्दू विरोधी हिंसा, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में जारी हिन्दू विरोधी उत्पीड़न व हिंसा की अगली कड़ी है। यूँ तो भारत के कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल आदि में भी जब तब कुछ ऐसा ही हो जाता है, जिस पर काबू पाने में भारतीय प्रशासन भी सियासी वजहों से लगभग असहाय नजर आता है।

गोया, इन घटनाओं से साफ है कि इन देशों में पुलिस या सैन्य प्रशासन का भय अपराधी या गिरोहबाज प्रवृत्ति के लोगों में नहीं है। ऐसा इसलिए कि सांप्रदायिक व जातीय वजहों से कुछ सुरक्षाकर्मी-पुलिसकर्मी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से ऐसी नृशंस घटनाओं को शह देते आये हैं। वहीं, सिविल प्रशासन पर भी अमूमन सियासी वजहें हावी रहती हैं, जिसके चलते भीड़ की बेलगाम हिंसा को रोकने वाला न तो कोई माई-बाप है और न ही ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई सामूहिक दंड विधान मौजूद है, जिसका भय इनके दिलोदिमाग में बना रहे।

इसलिए मेरे जेहन में यही सवाल उठता है कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप में कब तक थमेंगी सांप्रदायिक व जातीय हिंसा की ऐसी बर्बर आदिम युगीन घटनाएं? इस बदत्तर स्थिति के लिए भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हुक्मरान कितने जिम्मेदार हैं? वहीं, दुनिया के थानेदार मतलब अमेरिका, चीन और रूस आदि भी आखिर क्यों नहीं चाहते इन बर्बर घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक? शायद इसलिए कि लोकतांत्रिक सियासत में वोट बैंक के जुगाड़ के लिए ऐसी निर्लज्ज व जघन्य घटनाओं की ब्रेक के बाद पुनरावृत्ति जरूरी है!

तभी तो न तो मुगलिया सल्तनत में, न ब्रितानी हुकूमत में और न ही आजाद भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश में ऐसी लोमहर्षक घटनाओं पर कोई मजबूत लगाम लग सकी? तो क्या इन देशों का संविधान, संसद और सर्वोच्च न्यायालय इन सबकी खुली इजाजत देता आया है! यदि नहीं तो इन वारदातों के खिलाफ कितने स्वत: संज्ञान लिए गए। यहां की संसदों-विधानमण्डलों में कितनी सकारात्मक बहसें हुईं और उसके क्या सकारात्मक परिणाम निकले। क्या कोई जनरक्षक कानून बन पाया या विधि-व्यवस्था की विफलता के लिए किसी की जिम्मेदारी (सामूहिक ही सही) तय की जा सकी। जवाब होगा, शायद अब तक तो नहीं। तो फिर सवाल यही कि आजादी के इतने सालों बाद तक भी क्यों नहीं?

क्योंकि मुगलों और अंग्रेजों पर तो फूट डालो शासन करो के आरोप लगाए गए, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि में बैठे %काले अंग्रेजों,% जिनमें नेता-नौकरशाह दोनों शामिल हैं, ने क्या किया? जवाब होगा- हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई को सम्प्रदाय में बांटने के लिए अल्पसंख्यक-

बहुसंख्यकवाद चलाना और हिन्दू समाज को जातियों में बांटने के लिए आरक्षण को अनैतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और नख से सिख तक ब्राह्मणवाद-बनियावाद को कोसते रहने के शिवाय कुछ भी नहीं!

आखिर यह कौन नहीं जानता कि परस्पर कई युद्ध लड़ चुके इन देशों की राजनीति में जहां पाकिस्तान-बांग्लादेश की सियासत भारत और हिन्दू विरोध के ऊपर चलती आई है। वहीं भारत की सियासत मुस्लिम तुष्टीकरण और हिन्दू हितों की हिफाजत के नाम पर चमकती आई है। बावजूद इसके, कहीं आतंकी हिंसा, कहीं नक्सली हिंसा, कहीं गिरोह वार, कहीं जातीय हिंसा और कहीं साम्प्रदायिक हिंसा ही इन देशों की नियति बन चुकी है। यहां का पुलिस प्रशासन और मिलिट्री प्रशासन इन उपद्रवियों के समक्ष लाचार नजर आता है।

आप मानें या न मानें, लेकिन इस कबीलाई लोकतंत्र, जहां सुशासन के तमाम प्रयास विफल साबित प्रतीत हो रहे हैं, को अब पूंजीवाद से खतरा है। क्योंकि अपने दीर्घकालिक लाभ के वास्ते हथियार बेचते रहने की गरज से ये कहीं भी अमन-चैन रहने देना नहीं चाहते हैं! इनकी नीतियां जनद्रोही हैं, जिसे ये न्यू वर्ल्ड आर्डर करार देकर हम पर थोपना चाहते हैं। इनकी डिजिटल सोच सुविधाजनक पर रोजगार घाती है। इनका तकनीकी प्रेम विकासपरक लेकिन मानवता के लिए विनाशक है। इनकी नई आर्थिक नीति लूट-खसोट के अलावा कुछ भी नहीं!

यदि आप गौर करें तो रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, चीन-ताइवान विवाद, भारत-पाक क्षद्म युद्ध के बाद बांग्लादेश का हिन्दू विरोधी जिहाद कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग है और इसे समझने की जरूरत है। कभी नेपाल, कभी म्यांमार, कभी श्रीलंका, कभी मालदीव, कभी अफगानिस्तान, कभी ईरान आदि जगहों पर घटित अपेक्षित, अनपेक्षित घटनाओं का असर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ता है, जो वैश्विक महाशक्तियों के लिए सुस्वादु तरबूज प्रतीत होता है। इसलिए वो अपना हिस्सा पाने के लिए तरह तरह के तिकड़म भिड़ाते-भिड़वाते रहते हैं।

इसलिए सुलगता हुआ सवाल है कि जनतांत्रिक प्रशासन में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मजबूत रहते हुए और खबरपालिका के सजग रहते हुए भी आखिर ऐसी नृसंश वारदातें क्यों नहीं थम पा रही हैं? आखिर इससे किनका हित सध रहा है और उसे कबतक सधने दिया जाएगा? ये बातें सभ्य समाज के लोगों की नींद में खलल डाल रही हैं। इसलिए अब सबके जेहन में यह बात सुलग रही है कि यदि तमाम वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के बावजूद समकालीन शासन यदि मानव समुदाय को सुरक्षा और सुव्यवस्था देने में विफल रहता है तो फिर उसके होने या न होने का मतलब क्या रह जाता है? लिहाजा, शांति व सुव्यवस्था के सवाल पर अब सार्वजनिक बहस होनी चाहिए और करो या मरो का फैसला लेना चाहिए।

भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आते हैं, की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि भारत अपने बड़े भाई के तौर पर सख्त नहीं, बल्कि लचीला रुख अपनाने का आदी/अभ्यस्त रहा है। इसलिए तो हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर क्रमश: हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक दो देश तो बन गए, लेकिन कुछ मुस्लिम यहां रह गए और कुछ हिन्दू वहां रह गए। यही अब कोढ़ में खाज मानिंद लग रहे हैं।

आंकड़े चुगली करते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी तो बढ़ती रही, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दू आबादी घटती चली गई। आखिर ऐसा क्यों, यह पूछने का साहस भारतीय नेतृत्व के पास नहीं है और न ही जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत। अन्यथा हिंदुओं का उत्पीड़न पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी नहीं होता! भारत को अपने पड़ोसी देशों को साफ साफ बता देना चाहिए कि यदि हिन्दू हितों की हिफाजत नहीं कर सकते तो अपने अपने दूतावास भारत से समेट लो। फिर भी यदि उत्पात नहीं थमता तो सर्जिकल स्ट्राइक या सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखना चाहिए।

इतना ही नहीं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को तबतक के लिए समाप्त कर देना चाहिए, जबतक कि पाकिस्तान-बांग्लादेश का भारत में विलय नहीं हो जाए। यह सब कोई मजबूत इरादे वाला राजनेता ही करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अवसर है कि महात्मा गांधी की दुविधाओं से ग्रसित धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करके भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि यह हिंदुओं के हिस्से वाला भारत है। इसके साथ ही मुगलिया व ब्रितानी अत्याचारों के तमाम प्रतीकों को ध्वस्त करें। यह सब पंडित नेहरू के समय में ही हो जाना चाहिए, लेकिन अब यदि नरेंद्र मोदी भी इसे करने में चूक गए तो इतिहास उन्हें भी कतई माफ नहीं करेगा।

आप मानें या न मानें, पर आतताइयों को उनकी मांद में ठोक देना ही राजधर्म है, लेकिन रक्तरंजित न्यायपालिकाएं इसे अनुचित ठहराएँगी। यहां पर मैं रक्तरंजित न्यायपालिकाएं की उपमा इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि संविधान की संरक्षक संस्थाओं के तौर पर ये अपनी ऐतिहासिक भूमिकाओं के निर्वहन में सर्वथा विफल प्रतीत होती आई हैं।

अयोध्या उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दांव

शाहरुख खान

उत्तर प्रदेश में दस सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने हैं, अभी तारीखों का एलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन सीटों पर उतरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच, विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की कमान सांसद अवधेश प्रसाद को दी है। भाजपा से यहां की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। सपा के अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक रहते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद लल्लू सिंह को हराकर सांसद बने हैं।

अवधेश के साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर से प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सपा ने पांच अन्य सीटों पर भी उपचुनाव की तैयारियों के लिए दिग्गज उतार दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से दलित जाति के अवधेश प्रसाद पर दांव लगाया था और उनकी यह रणनीति सफल रही। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। दलित बहुल मिल्कीपुर सीट के लिए सपा ने अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाकर दलित-मुस्लिम और पिछड़ा समीकरण के जरिये अपनी व्यूह रचना की है। यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही टिकट मिलना तय माना जा रहा है। कटेहरी (अम्बेडकरनगर) में पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव, मझवां (मिर्जापुर) सीट की जिम्मेदारी सांसद वीरेंद्र सिंह और करहल (मैनपुरी) की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को दी गई है। फूलपुर सीट के लिए विधायक व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज और सीसामऊ (कानपुर नगर) के लिए विधायक राजेंद्र कुमार को प्रभारी नामित किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन प्रभारियों को बूथ स्तर पर सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा है। पार्टी हाईकमान ने अपने प्रभारियों को हर बूथ पर पांच सक्रिय यूथ तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ये यूथ संबंधित बूथ पर घर-घर जाकर संविधान और आरक्षण के महत्व को समझाएंगे। विधानसभा प्रभारी, बूथ स्तर के इन सक्रिय कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहेंगे। सपा नेताओं का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक को चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली तक विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

संकट की छाया के कारण राजनीतिज्ञों में दूरदर्शिता जरूरी

शंकर अय्यर

बहुत पुरानी बात नहीं है, जब बांग्लादेश को सफलता की एक शानदार कहानी के रूप में पेश किया गया था। राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ पर राजनीतिक पंडितों ने इतिहास, भूगोल और परिस्थितिगत चुनौतियों वाले राष्ट्र में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का जश्न मनाया। भारत में इस बात पर बहस चल रही थी कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है, जिस पर हमारे देश में नाराजगी भरी टिप्पणियां सामने आती थीं। लेकिन हाल में बांग्लादेश इससे इतर गलत कारणों से सुर्खियों में आया, जो थे- भ्रष्टाचार, कोटा राजनीति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और असमानता।

लोकतंत्र में सीखने की अवस्था एक तानाशाही शासन के नैरेटिव को समझने की सीमाओं को दर्शाती है। बांग्लादेश में मुद्रास्फीति 9.72 फीसदी के साथ दहाई अंकों के करीब पहुंच गई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। करीब 45 दिनों के आंदोलन के दौरान 400 से ज्यादा लोगों की मौत, शासन में परिवर्तन और शेख हसीना के घर का सामान लेकर भागते प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों ने बांग्लादेश की ब्रांड छवि को ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रभावित तो हुई ही है, सीमापार आतंकवाद के साथ घुसपैठ व शरणार्थियों की समस्या में भी वृद्धि हो सकती है।

ढाका से 7,900 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बसा है ब्रिटेन का खूबसूरत शहर डरहम, जहां व्यवसायों को तबाह करने के लिए कारों का इस्तेमाल किया गया। पूरे ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन और नफरती अपराध ने बीस अन्य शहरों को हिलाकर रख दिया, जिससे 2011 के बाद से सबसे बड़ा कानून-व्यवस्था का संकट पैदा हो गया। बांग्लादेश के विपरीत उन्नत अर्थव्यवस्था माने जाने वाले ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धी राजनीति मजबूत है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आए कीर स्टार्मर की सरकार को मुश्किल से छह हफ्ते बाद ही गृहयुद्ध का सामना करना पड़ रहा है।

अराजकता का एक दिलचस्प पहलू एक्स (पहले ट्वीटर) के मालिक एलन मस्क और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच टकराव है। एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि गृहयुद्ध अनिवार्य है, जबकि स्टार्मर ने प्रदर्शन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा देने वालों को चेतावनी दी थी। विरोध प्रदर्शन के पीछे यह अवधारणा है कि प्रवासी रोजगार के अवसरों को हड़प रहे हैं और स्थानीय लोगों की अनदेखी हो रही है।

विडंबना देखिए कि जिस ब्रेग्जिट को समाधान बताया गया था, उसने व्यापार, निवेश और विकास के नुकसान के बाद स्थितियों को और बदतर बना दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये गुस्से को भड़काया जा रहा है। गलत सूचना ने समाज को बांट दिया है। दुखद है कि जो लोग अपने हालात बदलने में असमर्थ हैं, उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा अपनी ही तरह के अन्य कमजोर लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भड़काया जा रहा है। आम तौर पर प्रासंगिकता और सत्ता के आकांक्षी लोग एक राय को सार्वभौमिक राय के रूप में पेश करने में प्रेरक होते हैं और शोध से पता चलता है कि युद्ध हो या सामाजिक संघर्ष,?दोनों में समीकरण कुछ इस तरह बन जाते हैं, जो ध्रुवीकरण और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देते हैं। पहली नजर में ब्रिटेन और बांग्लादेश दो अलग-अलग संस्कृतियां, अर्थव्यवस्थाएं और लोकतंत्र हैं। लेकिन दोनों की साझा समस्या युवा बेरोजगारी है। ब्रिटेन में 18 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 12 फीसदी है और पांच लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। बांग्लादेश में 3.2 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार या शिक्षा से वंचित हैं। 1970 के दशक में, येल के प्रोफेसर और लिंडन जॉनसन के सलाहकार आर्थर ओकुन ने %दुख सूचकांक% की अवधारणा पेश की थी। सूचकांक की गणना वार्षिक बेरोजगारी दर और वार्षिक मुद्रास्फीति दर को जोड़कर की जाती है। दुख का बढ़ना आंदोलन और अराजकता को बढ़ावा देने वाला सामान्य कारक है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में दुख का एक नया नाम है, जीवन-यापन की लागत का संकट। और यह पूरे ब्रिटेन में स्पष्ट है, जहां किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ लोगों के घरों पर बैंकों द्वारा कब्जा करने की घटनाएं पांच साल के उच्चतम स्तर पर हैं।

यह सिर्फ बांग्लादेश और ब्रिटेन की बात नहीं है, बल्कि इस दुख ने दुनिया भर में राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दिया है। कार्नेगी एंडोमेंट के ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर से पता चलता है कि 2017 से अब तक 258 देशों में आर्थिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश में, कई लोगों की कीमत पर कुछ लोगों के अधिकारों के खिलाफ यह दुख, गुस्से में बदल गया, जबकि ब्रिटेन में यह नफरती हिंसा में बदल गया है, जो नस्ल और संस्कृति के मामले में बाहरी माने जाने वाले लोगों को निशाना बनाता है। असमानता से उपेक्षा की भावना बढ़ जाती है, जो अवसरों की कमी से और बदतर हो जाती है, जिससे आय का अंतर भी बढ़ जाता है। असमानता एक जटिल आर्थिक मुद्दा है, जो राजनीतिक आक्रोश को कई गुना बढ़ाने वाला कारक है। वैश्विक स्तर पर ट्रैक किए गए ग्रेट गैट्सबी कर्व से पता चलता है कि समाज के समृद्ध तबके के पास धन इकट्ठा होने से गतिशीलता अवरुद्ध होती है। जनरेटिव एआई की विघटनकारी क्षमता पहले से ही काम कर रही है और अब तो आईएमएफ का भी अनुमान है कि वैश्विक रोजगार का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण खत्म हुआ है। डिजिटलाइजेशन ने मानव रोजगार को कम कर दिया है, खासकर बैंकिंग और खुदरा क्षेत्र में। जलवायु, प्रौद्योगिकी एवं जनसांख्यिकी जैसे व्यवधानों की तिकड़ी अनिश्चितता बढ़ाती है।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का पश्चिम से संबंध

राजेश बादल

अमेरिका उतावला है। भारतीय उपमहाद्वीप में वह अपना ताकतवर सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। चीन और रूस की घेराबंदी के लिए दशकों से वह जगह की खोज में है। पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका में चीन और भारत के कारण उसकी दाल नहीं गली। भारत में मजबूत लोकतंत्र और सार्वभौमिकता के मद्देनजर बात नहीं बनी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद से उसने तीन वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा सेंट मार्टिन द्वीप खरीदना चाहा। वहां से भी उसे टका सा जवाब मिल गया। इस पर बौखलाए अमेरिका ने बांग्लादेश में फौज की मदद से उनकी सरकार गिरा दी। अमेरिका की यह पुरानी तरकीब है। कम-से-कम शेख हसीना तो यही कहती हैं। अपदस्थ किए जाने के बाद पहली बार उन्होंने मुंह खोला है।

उन्होंने कहा है कि अमेरिका की इच्छा पूरी नहीं करने के कारण उन्हें अपनी निर्वाचित सरकार खोनी पड़ी है। अगर वे ऐसा नहीं करतीं तो मुल्क में रक्तपात और व्यापक हिंसा की आशंका थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि वे अमेरिका की ख्वाहिश के अनुसार काम करतीं तो न उनकी सरकार जाती और न मुल्क में खून-खराबा होता। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने जो भी फैसला किया, वह बांग्लादेश की भूमि बचाने के लिए किया।

उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही स्वदेश लौटेंगी और देशवासियों की एक बार फिर सेवा करेंगी। बता दूं कि लगभग तीन साल पहले भी यह द्वीप अमेरिका को देने का मामला संसद में उठा था। बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान ने इस मामले को उठाया था। इस द्वीप को अमेरिका को देने के लिए खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था। इस बार तख्तापलट के पीछे यही सौदेबाजी है। यह अवामी लीग का दावा है। अब पाकिस्तान का उदाहरण देखिए। अमेरिका में एक गोपनीय दस्तावेज से खुलासा हुआ था कि जो बाइडेन सरकार के इशारे पर इमरान खान की निर्वाचित सरकार गिराई गई थी। इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका ने उनसे भी पाकिस्तान में अपना सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत देने के लिए कहा था। चीन के दबाव में इमरान खान ने इनकार कर दिया।

यही नहीं, अमेरिकी राजदूत की बात अनसुनी करके वे फरवरी 2022 में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने मास्को चले गए। बकौल इमरान वे रूस से सस्ता क्रूड आयल खरीदने के लिए बातचीत करने गए थे, जैसा कि भारत करता है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना की मदद से इमरान की सरकार गिरा दी। अमेरिका पहले भी नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में यह प्रस्ताव रख चुका है। वह सैनिक संधियों के जरिये अपना अड्डा कराची के आसपास बनाना चाहता है। इमरान खान चीख-चीख कर कहते रहे कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। उनके पास पर्याप्त सुबूत हैं। लेकिन इस क्रिकेटर रहे प्रधानमंत्री की किसी ने नहीं सुनी? अंतत: वे जेल में डाल दिए गए। माना जा सकता है कि वे तब तक सलाखों के पीछे रहेंगे, जब तक अमेरिका चाहेगा। अब इमरान की पार्टी के लोग अमेरिकी राजनेताओं से माफीनामा भेज रहे हैं मगर अमेरिका के कान पर जूं नहीं रेंग रही। अमेरिका का यही तरीका है। इमरान खान ने तो चीन को भी नाराज कर लिया था। चीन ने भी इस मामले में चुप्पी साधे रखी। आमतौर पर चीन संवेदनशील मामलों में मुंह नहीं खोलता। पाकिस्तान में सेना इस परिवर्तन के पीछे थी और बांग्लादेश में भी आईएसआई के माध्यम से बांग्ला सेना ने शेख हसीना को चलता किया।

आईएसआई ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो शेख हसीना वाजेद की सरकार गिरा दी और दूसरा हिंदुओं के खिलाफ विष वमन कर बांग्लादेश की अवाम को भारत के खिलाफ भड़काने का काम किया। अब वह अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश में भारतीय निकटता के सारे सुबूत मिटाने के प्रयास कर रही है।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बांग्लादेश का घटनाक्रम देखें तो जो बाइडेन की राष्ट्रपति पद से उम्मीदवारी से हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के लिए संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन्हें कश्मीर के मामले में पाकिस्तान समर्थक सांसदों का समर्थन भी मिल रहा है। यह पार्टी अमेरिका की परंपरागत विदेश नीति पर ही चलने की पक्षधर है।

ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ-साथ आना उनके लिए फायदेमंद है। कमला भले ही भारतीय मूल की हों, लेकिन वे भारत की कश्मीर नीति की मुखर आलोचक रही हैं। बांग्लादेश में अमेरिका समर्थक सरकार आने से उसका रौब समूचे उपमहाद्वीप पर पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प चीन के कट्टर आलोचक हैं। आप उन्हें चीन का दुश्मन कह सकते हैं।

मगर बराक ओबामा, जो बाइडेन और कमला हैरिस चीन से रिश्तों में सुधार भी चाहते हैं। ताइवान के मामले में गंभीर मतभेद होते हुए भी डेमोक्रेट्स चीन से अच्छे नहीं तो सामान्य संबंध चाहते हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिले भी हैं। चीन चाहेगा कि वहां ट्रम्प की वापसी नहीं हो लेकिन बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम से शायद चीन की पेशानी पर बल पड़ें। फिर भी वह चाहेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आए।

ऐसे में इन शिखर ताकतों के बीच कूटनीतिक संबंधों का नए सिरे से निर्धारण हो सकता है। भारत के लिए बांग्लादेश का घटनाक्रम निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। उसके लिए अनेक मोर्चे एक साथ खुल गए हैं। अमेरिका ने दोस्त होने का दम भरते हुए भी बांग्लादेश में भारत हितैषी सरकार गिरा दी तो यह दोस्ती वाला धर्म तो नहीं निभाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हेकड़ी देखने लायक होगी।

भारत को पूरब और पश्चिम दोनों सीमाओं पर सतर्क रहना होगा। उत्तर में चीन ने पहले से ही भारतीय परेशानी बढ़ा रखी है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ कारोबार को तगड़ा झटका लगेगा। लगभग पंद्रह अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच है। इसके अलावा रेल संपर्क, सड़क संपर्क, बिजली उत्पादन, दाल निर्यात और रक्षा संबंधी कई समझौते चल रहे हैं। अब पाकपरस्त सरकार की नीति पर सब कुछ निर्भर करेगा।

फिल्मों से अलग है राजनीति की कंगना

प्रभु चावला

कंगना रनौत का रहस्य यह है कि वे कोई रहस्य नहीं हैं। वे डिजाइनर साड़ी में लिपटीं एक पहेली हैं, जिन्हें सोशल मीडिया में लोकप्रिय उपस्थिति के साथ नये राजनेता से नैतिक पहरेदार बने व्यक्ति के रूप में रहस्यात्मक ढंग से स्वीकार कर लिया गया है। राजनीति में कई स्त्रियां हैं, पर 38 साल की यह अभिनेत्री अलग ही है। अपने आदर्श और विचारधारा के विरोधियों के विरुद्ध उनके तीखे हमले इंगित करते हैं कि एक लड़ाकू भगवा योद्धा का आगमन हो चुका है। उनका व्यक्तित्व अवचेतन के स्तर पर स्वयं को झांसी की रानी से जोड़ता है। लेकिन बॉलीवुड की इस रानी को बलिदान नहीं देना है, बस लड़ना है। वे अपने आदर्श नरेंद्र मोदी के दृढ़ व्यक्तित्व से आकर्षित होकर छह साल पहले भाजपा से संबद्ध हुई थीं, जिन्होंने उन्हें उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। उनकी जीत उनके जीवन का रूपक भी है- सिनेमा और पार्टी में वे बाहरी होकर भी सफल रही हैं। वे भले बहुत अधिक नहीं बोलती हैं, पर पहली बार सांसद बने भाजपा के कई नेताओं से कहीं अधिक मुखर हैं। कंगना को बॉलीवुड के शाही लोग या भाजपा की सांगठनिक पदक्रम भले न स्वीकारें, पर उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 44 फिल्में की हैं, जिनमें छह सुपरहिट रहीं। उनकी पिछली फिल्म 'तेजस' को दर्शकों ने नकार दिया। अब बदली हुई भूमिका में कंगना की महिमा के आधार उनके आदर्श मोदी हैं। वे कैसे संसद में बैठे अन्य फिल्मी सितारों से अलग हैं, जो केवल परदे पर नाटकीय संवाद बोलते हैं? उनकी सफल फिल्में दृढ़ स्त्रियों पर केंद्रित रही हैं, जो पितृसत्ता को परास्त करती हैं। अब वे मोदी के अभिजन-विरोधी अभियान में एक प्रभावी सहयोगी कलाकार की भूमिका में हैं। शेक्सपियर ने लिखा है कि दुनिया एक रंगमंच है और सभी लोग अभिनय करते हैं तथा सबके आने-जाने का समय निश्चित है। कंगना जानती हैं कि मंच पर पदार्पण कैसे किया जाता है। राहुल गांधी के विरुद्ध दिये गये उनके बयान न केवल राजनीतिक रूप से गलत हैं, बल्कि उनकी भाषा भी ठीक नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के एक अत्यंत आपत्तिजनक मीम को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा- 'जातिजीवी, जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है।' वे शाकाहारी हैं, पर विरोधियों का कीमा बना देना चाहती हैं। इंडी अलायंस का पसंदीदा काम मोदी की आलोचना करना है, तो कंगना राहुल गांधी को निशाना बनाकर भाजपा के अघोषित वैचारिक लड़ाके की भूमिका निभा रही हैं। एक बयान में उन्होंने कहा- 'अपनी जात का कुछ अता पता नहीं, नानू मुस्लिम, दादी पारसी, मम्मी क्रिश्चियन और खुद ऐसा लगता है जैसे पास्ता को कढ़ी पत्ते का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की हो, और इनको सबकी जात पता करनी है।' एक दूसरे बयान में कंगना ने कहा- 'राहुल गांधी में कोई आत्मसम्मान नहीं है, कल वे कह रहे थे कि हम शिवाजी की बारात हैं और यह चक्रव्यूह है। मुझे लगता है, उनकी जांच होनी चाहिए कि कहीं वे नशे का सेवन तो नहीं कर रहे। होश में कोई व्यक्ति ऐसे बयान नहीं दे सकता।' यह बयान ध्यान देने योग्य है क्योंकि अतीत में कंगना नशे की लत छोड़ने के लिए उपचार करा चुकी हैं। कंगना हर मामले, चाहे वह कूटनीति का हो या राजनीति का, में हिंदू आयाम जोड़ देती हैं। जब शेख हसीना भारत आयीं, तो कंगना ने दावा किया- 'भारत पड़ोस के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हमें इस बात का गर्व और खुशी है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पर जो लोग भारत में रहते हैं और पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों, उन्हें समझ जाना चाहिए कि क्यों। मुस्लिम देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम भी नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रहते हैं। जय श्री राम।' कंगना अन्य सांसद कलाकारों की तरह अपने नये अवतार को बर्बाद नहीं करना चाहती हैं।

पर्सनल स्पेस में प्रोफेशनल लाइफ हो रही है हावी तो इन टिप्स को करें फॉलो

वर्क-फॉम-होम और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल के चलते प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ खराब होने लगी है। कंपनी को ऐसा लगता है कि वर्क-फॉम-होम और हाइब्रिड वर्किंग के कारण वह अपने इंप्लाई को कभी भी फोन कर सकते हैं और उन्हें कभी भी काम करने को कह सकते हैं। ऐसे में मजबूरी में अपनी नौकरी को बचाने के लिए इंप्लाई को ओवरटाइम काम करना पड़ता है। यहीं कारण है जिसके कारण पर्सनल लाइफ के लिए आजकल के युवा को समय नहीं मिलता है और उनकी लाइफ में दिक्कत आने लगती हैं। हालांकि कुछ टिप्स को अपनाकर आप भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को अलग रख सकते हैं।

शेड्यूल बनाएं

अगर आप वर्क-फॉम-होम और हाइब्रिड वर्किंग के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको समय पर लॉग इन करना चाहिए और समय पर ही लॉग आउट करना चाहिए। अगर आपका बॉस आपको रोजाना ओवरटाइम काम करने को कह रहा है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए।

ब्रेक लें

वर्क-फॉम-होम और हाइब्रिड वर्किंग में आपको काम के साथ बीच- बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। आधे घंटे का ब्रेक लेकर आप खुद के काम को कर सकते हैं। इससे आपको खुद के लिए भी समय मिलता रहेगा।

परिवार के लिए समय

कई बार ऑफिस का काम होने के बाद लोग अपने फोन यानी सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि आपको स्क्रीन टाइम कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बचा हुआ समय आपको परिवार को देना चाहिए या फिर आप नई चीजों को सीखने के लिए भी समय निकाल सकते हैं।

काउंसलिंग लें

अगर आप इन चीजों को फॉलो करने के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल स्पेस से अलग नहीं रख पा रहे हैं तो आपको काउंसलिंग लेने की जरूरत है। काउंसलिंग की मदद से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल स्पेस में हावी नहीं होने देगें।

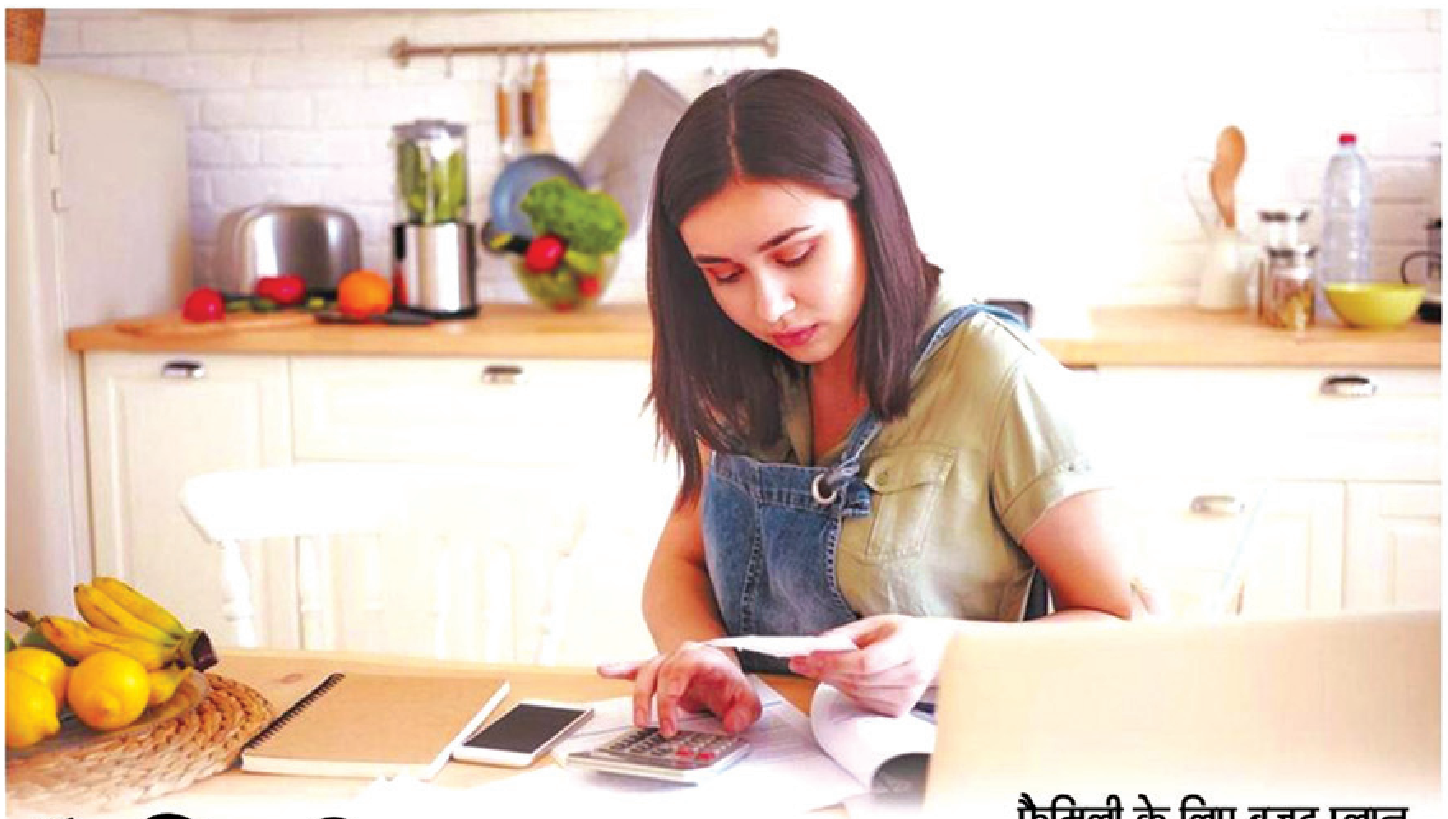

फैमिली बजट प्लान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

फैमिली के लिए बजट प्लान करना यकीनन एक टफ टास्क है, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने इस काम को बहुत आसान बना सकती हैं।

अधिकतर घरों में लोगों को यह शिकायत रहती है कि महीना खत्म होते-होते खर्च के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे अपने फैमिली बजट का ध्यान नहीं रखते हैं। जब परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हों या फिर बच्चे हों तो ऐसे में फैमिली बजट पर अतिरिक्त ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ लोग महीने की शुरुआत में फैमिली बजट तो बनाते हैं लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे कुछ छोटी-छोटी बातों को मिस कर जाते हैं। फैमिली बजट बनाने का मतलब सिर्फ जरूरी खर्चों की लिस्टिंग करना ही नहीं है, बल्कि आपको अतिरिक्त खर्चों से लेकर बचत, इमरजेंसी फंड व इनवेस्टमेंट आदि को भी इसमें शामिल करना जरूरी होता है। आपको फैमिली बजट बनाने में कोई समस्या ना हो और बाद में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में बता रहे हैं-

इनकम की बनाएं लिस्ट

जब आप फैमिली बजट बना रहे हैं तो आपको अपनी महीने की आमदनी का पता होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी इनकम की लिस्ट बनाएं। इसमें आप सैलरी के अलावा अन्य किसी भी आय के स्त्रोत से मिलने वाले पैसों का शामिल करें। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हर महीने आपकी पॉकेट में कितने पैसे आ रहे हैं।

खर्चों की बनाएं लिस्ट

जब आप अपनी इनकम की लिस्ट बना लें तो उसके बाद खर्चों की लिस्ट तैयार करें। इसमें आप घर के किराए से लेकर बच्चों की फीस, राशन, ईएमआई व अन्य अतिरिक्त खर्चों को शामिल करें। इनकम और खर्च की लिस्ट बनाने से आपको एक रिएलिटी चेक मिलता है। साथ ही इससे फैमिली बजट बनाना अधिक आसान हो जाता है।

सेट करें फाइनेंशियल गोल्स

फैमिली बजट बनाने का मतलब सिर्फ आमदनी और खर्चों पर ही नजर रखना नहीं है। बल्कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी सेट करना चाहिए। आप इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे वेकेशन से लेकर इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे घर की डाउन पेमेंट से लेकर बच्चों की पढ़ाई व रिटायरमेंट आदि को भी जरूर शामिल करें।

तैयार करें प्लान

फैमिली बजट बनाते समय आपको एक सही प्लानिंग के साथ चलना बेहद जरूरी है। मसलन, जब आप बजट बनाएं तो अपने खर्चों को अलग-अलग कैटेगिरीजैसे ग्रॉसरी से लेकर सेविंग आदि में बांट लें। इस तरह आप हर कैटेगिरी व गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी आय को बांट दें। कोशिश करें कि आप अपनी आय का 50 प्रतिशत ज़रूरतों, 30 प्रतिशत इच्छाओं और 20 प्रतिशत बचत आदि के लिए रखें। इससे आपको कभी भी पैसों को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी।

जरूर करें ट्रैक

अगर आप चाहती हैं कि आप अपने लिए एक सही फैमिली बजट बना पाएं, तो इसके लिए आपको उसे ट्रैक जरूर करें। एक बार जब आप बजट बना लें तो उसके बाद आमदनी व खर्चों दोनों को ट्रैक करते रहें। जब आप इनका रिकॉर्ड रखते हैं तो इससे आपको अपने फैमिली बजटको सही तरह से एडजस्ट करने में मदद मिलती है। अगर आपके लिए हर दिन का ब्यौरा रखना मुश्किल लगता है तो ऐसे में आप बजटिंग टूल व ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

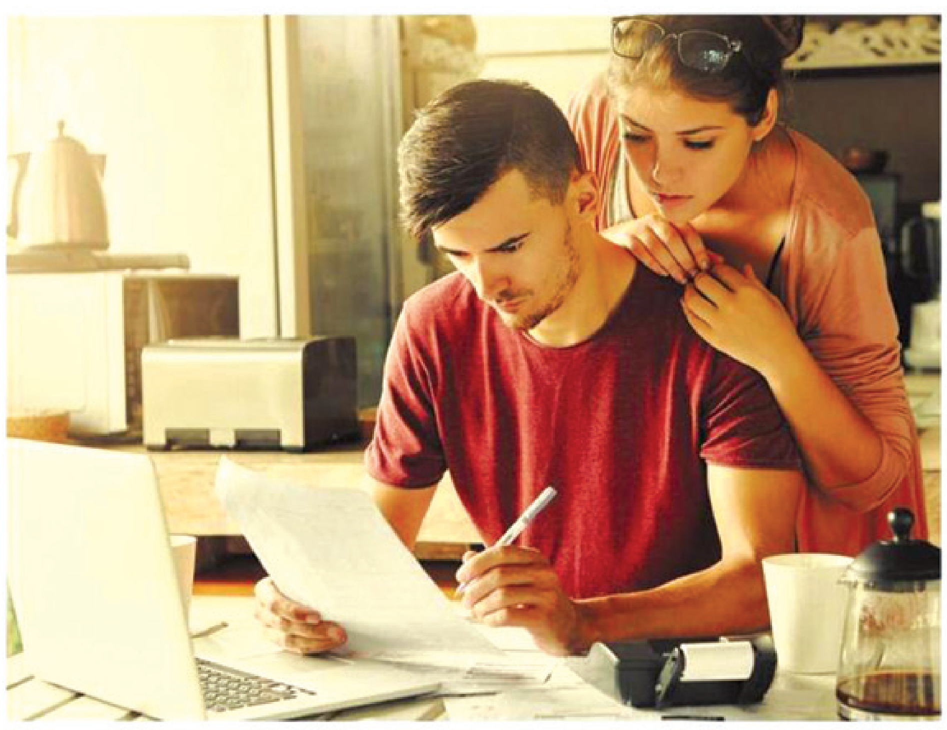

इन चार वजहों से मशीन वॉश करने के बाद कपड़ों पर नजर आते हैं सफेद दाग

कपड़े किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। अगर हम साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं तो इससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ता है। यही कारण है कि लोग एक बार पहनने के बाद कपड़ों को मशीन वॉश करना पसंद करते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कपड़ों को मशीन वॉश करते हैं तो अक्सर उनमें सफेद दाग नजर आते हैं। कपड़ों को धोने के बाद भी जब उन पर सफेद धारियां या धब्बे नजर आते है तो यकीनन मन में एक निराशा पैदा होती है। ऐसे में कपड़ों को दोबारा धोने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन कपड़ों के पूरे बैच को दोबारा धोना यकीनन काफी समय लेने वाला होता है। हालांकि, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मशीन में कपड़े धोने के बाद भी उनमें सफेद दाग क्यों नजर आते हैं। दरअसल, इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं।

पाउडर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना

कपड़ों को धोने के बाद उन पर सफ़ेद दाग नजर आने का एक मुख्य कारण पाउडर डिटर्जेंट का उपयोग है। अक्सर पाउडर डिटर्जेंट मशीन के पानी में उस तरह से घुलता नहीं है जैसा उसे घुलना चाहिए, जिससे कपड़ों पर धारियां पड़ जाती हैं। इसलिए, अगर आप कपड़ों पर नजर आने वाले इस सफेद दाग की समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं तो पाउडर डिटर्जेंट से लिक्विड डिटर्जेंट पर स्विच करने पर विचार करें।

डिटर्जेंट का अधिक इस्तेमाल करना

कपड़ों का धोते समय डिटर्जेंट की मात्रा भी बहुत मायने रखती है। कई बार लोग बेहतर सफाई के चक्कर में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने से अवशेष रह सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से घुल नहीं सकता या धोने के दौरान बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए, आप सीमित मात्रा में ही डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। अगर आपके कपड़ों पर किसी तरह के दाग है तो डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ाने के स्थान पर पहले स्पॉट ट्रीटमेंट की मदद से दाग को क्लीन करें।

मशीन ओवरलोड होना

अमूमन लोग एक बैच में ज्यादा से ज्यादा कपड़े धोने की कोशिश करते हैं, जिससे समय की बचत हो सके। लेकिन वास्तव में इसका खामियाजा कपड़ों को भुगतना पड़ता है। ओवरलोड वॉशिंग मशीन पानी के फ्लो और ड्रेनेज को बाधित कर सकती है। इसलिए, डिटर्जेंट पूरे लोड तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कपड़े सही तरह से धुल नहीं पाते हैं। कपड़ों पर बची हुई गंदगी, झाग, धूल के कारण सफेद अवशेष रह जाते हैं। ऐसे में उन कपड़ों को दोबारा धोना पड़ता है। इसलिए, आप अपनी मशीन में बहुत ज्यादा पानी न भरें, चाहे आपके पास समय की कमी क्यों न हो।

मशीन ड्रेनपाइप फ़िल्टर का बंद होना

अक्सर हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता है, लेकिन मशीन ड्रेनपाइप फ़िल्टर बंद हो जाने की स्थिति में लिंट, अघुलनशील डिटर्जेंट और गंदगी आपके कपड़ों पर फिर से जम सकती है। इसलिए, नियमित अंतराल पर फ़िल्टर को साफ़ करने का नियम बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अधिक बेहतर साफ होते हैं।

डाइनिंग स्पेस को है सजाना, इन छोटी-छोटी चीजों को न करें इग्नोर

डाइनिंग एरिया एक ऐसी जगह है, जहां पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर न सिर्फ खाना खाते हैं, बल्कि कुछ हंसी-खुशी के पल भी बांटते हैं। यूं तो परिवार के सदस्यों का एक साथ होना ही उस जगह को जीवंत बना देता है, लेकिन अगर डाइनिंग एरिया के डेकोरेशन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कहना ही क्या। वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्ति हाथों से पहले आंखों से खाता है, इसलिए भोजन के साथ-साथ डाइनिंग एरिया के लुक्स पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आप खाना खाने बैठे और वहां पर सब कुछ बिखरा या रूखा-रूखा सा हो तो पहले ही मूड ऑफ हो जाता है। वहीं अगर डाइनिंग एरिया को करीने से सजाया गया हो तो व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है। वैसे डाइनिंग एरिया को सजाने के लिए बहुत करने की आवश्यकता नही होती। अगर आप अपनी टेबल पर कुछ चीजों को रख दें तो इससे टेबल की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है।

कालीन

डाइनिंग एरिया में कलर एड करने और उसे खूबसूरत बनाने के लिए कालीन का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। आप डाइनिंग एरिया में कॉन्ट्रास्टिंग कलर के कालीन को बिछाएं। वैसे आप कालीन के फैब्रिक और प्रिंट्स में भी कई ऑप्शन चुन सकती हैं, जो आपके डाइनिंग एरिया को खूबसूरत बनाएंगे।

ताजे फल

फलों को स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है और अगर आप डाइनिंग टेबल को हेल्दी तरीके से सजाना चाहती हैं तो ताजे फलों का इस्तेमाल करना एक अच्छा आईडिया है। ताजे फलों के कारण आपका डाइनिंग टेबल देखने में तो अच्छा व कलरफुल लगता है ही, साथ ही इससे घर के सदस्य फल खाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। आप फलों को सिरामिक, लकड़ी के बाउल या खूबसूरत प्लेटर में रखकर सजा सकती हैं।

खूबसूरत नैपकिन रिंग

डाइनिंग टेबल पर नैपकिन की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन अगर इसे सही तरह से रखा जाए तो इससे डाइनिंग टेबल की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। आजकल मार्केट में कई बेहद खूबसूरत डिजाइन की नैपकिन रिंग्स मिलती हैं, जिसमें आप नैपकिन को रख सकती हैं। इन डिजाइन में आपको लीफ, फ्लॉवर, पर्ल, विंटेज और कई अन्य तरह के डिजाइन्स चुन सकती हैं।

मिरर

डाइनिंग एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए सामने वाली दीवार पर मिरर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे डाइनिंग स्पेस बड़ा लगता है, साथ ही जब आप डाइनिंग स्पेस में मिरर का इस्तेमाल करती हैं तो इससे उस स्पेस को मॉडर्न व कंटेपररी लुक मिलता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

खटाखट-फटाफट वाले हो गए गायब, चुनाव में आएंगे नजर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल-मई के महीने में आपने खटाखट स्कीम के बारे में सुना होगा, लेकिन अब लोगों का कोई अता पता नही हैं। उन्होंने कहा कि अब ये लोग फिर से चुनावी मौसम में नजर आएंगे। अपना हमला जारी रखते हुए योगी ने कहा कि लोगों से एक-एक लाख रुपये के बॉन्ड भरवाए गए थे। हर महीने 8500 रुपये भेजने का वायदा किया गया था, लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता-पता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि प्रत्येक गरीब परिवारों की एक महिला के खाते में तब तक एक लाख रुपये डाले जाएंगे, जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता।

यूपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बढ़ा दी सपा की टेंशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उन 10 सीटों में से पांच सीटें मांगी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में बोलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को राज्य में अपनी पांच सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी सीटें पुरानी पार्टी को दी जानी चाहिए। इस बीच, सोमवार को विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में शामिल दोनों दलों ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने-अपने प्रभारियों की घोषणा की। सपा ने छह सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा की, जबकि कांग्रेस ने सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा की। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कटेहरी सीट के प्रभारी होंगे।

15 अगस्त को दिल्ली में झंडा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी

नई दिल्ली। दिल्ली में 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा नहीं फहरा सकेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। केजरीवाल के निर्देश पर गोपाल राय ने पत्र भेजा था। जिसका जवाब विभाग की ओर से आ गया है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि झंडा अरविंद केजरीवाल फहरा सकते हैं। 15 अगस्त को झंडा फहराने के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय को लिखे पत्र के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिखा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरोक्त संचार (मंत्री का पत्र) जेल के बाहर भेजे जाने वाले अनुमेय संचार की श्रेणी में नहीं आता है। ऊपर बताए गए नियमों के उल्लंघन में कोई भी लिखित या मौखिक संचार कानूनी रूप से वैध नहीं है। इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की उपलब्धता के लिए उनकी सुविधा मांगी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला

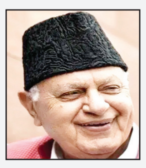

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग इस महीने के अंत तक चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब्दुल्ला ने ये टिप्पणियां डोडा जिले में एक पार्टी समारोह के दौरान कीं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होने तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। अब्दुल्ला ने कहा, वह मौजूदा व्यवस्था के तहत चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं क्योंकि मैं मरा नहीं हूं। जब अब्दुल्ला से उनके चुने हुए निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैं आपको पहले से क्यों बताऊं? एक जनरल अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करता और मैं भी एक जनरल हूं और लड़ने के लिए तैयार हूं।

ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल को सरकारी अस्पताल के सेमिनल हॉल के अंदर एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के संबंध में पूछताछ करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए था। अपराध पर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया कि प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को उनके इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में क्यों नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने प्राचार्य को त्यागपत्र देने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य के वकील से कहा, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? उसका बयान दर्ज करें। वह जो भी जानता है उसे बताने दें। अदालत ने बलात्कार और हत्या को इतना वीभत्स भी कहा। अदालत ने कहा कि हम प्रेस का मुंह नहीं बंद कर सकते। आप (राज्य) डॉक्टरों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? वे आहत हैं। हादसा बहुत वीभत्स है।

वक्फ बिल: जेपीसी की अध्यक्षता करेंगे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल

■ **31 लोगों की बनी है समिति**

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अध्यक्षता करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पेश किया था और सदन में प्रस्तावित संशोधनों पर संक्षिप्त चर्चा हुई थी। विधेयक को आगे की जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम में बदलाव करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत 8.5 लाख संपत्तियां आती हैं।

भाजपा के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने विधेयक का पूरा समर्थन किया, हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी) और एआईएमआईएम सहित विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। उल्लेखनीय है कि जेपीसी, एक तदर्थ संसदीय समिति है, जिसका गठन 31 सदस्यों के साथ किया गया है, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। लोकसभा में पैनल के 12 सदस्य सत्तारूढ़ एनडीए से हैं, जिनमें से आठ भाजपा से हैं। इसके अलावा, जेपीसी के नौ सदस्य विपक्ष से हैं। जेपीसी में लोकसभा सदस्य जगदंबिका पाल (अध्यक्ष), निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, डीके अरुणा हैं। ये सभी सदस्य भाजपा से हैं।

कांग्रेस से गौरव गोगाई, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद को इसका सदस्य बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सदस्य मौलाना मोहिबुल्ला नदवी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, द्रमुक के ए. राजा, तेलुगू देसमपार्टी (तेदेपा) के लावू श्रीकृष्णा, जनता दल (यूनाइडेड) के दिलेश्वर कामत, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के सुरेश गोपीनाथ महत्रे, शिवसेना के नरेश गणपत म्हास्के, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अरुण भारती और एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवैसी भी इस समिति में शामिल हैं।

लोकसभा ने इसके साथ ही राज्यसभा से अनुशंसा की कि वह इस संयुक्त समिति के लिए 10 सदस्य का चयन कर निचले सदन को सूचित करे। बाद में राज्यसभा में रीजीजू ने यह प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। रीजीजू ने उच्च सदन में बताया कि राज्यसभा से इस समिति में बृजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधामोहन दास अग्रवाल (सभी भाजपा), सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस), मोहम्मद नदीमुल हक (तृणमूल कांग्रेस), वी विजय साई रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस), एम मोहम्मद अब्दुल्ला (द्रमुक), संजय सिंह (आम आदमी पार्टी) और डी वीरेंद्र हेगड़े (मनोनीत) को शामिल किया गया है।

वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों पर बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना की घोषणा की है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी फैसला किया है। खान ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में 2023-24 में बहुउद्देश्यीय भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए दस परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

जमा खान ने कहा कि 2005 के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मदरसे में आधुनिक समय में जरूरी सभी सुविधाएं हों। उन्होंने कहा कि मदरसा एक शिक्षण संस्थान है। इसके छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना होती है। हमारे नेताओं ने इसे सुनिश्चित किया। वक्फ की संपत्तियां समाज के गरीब तबके के विकास के लिए हैं। हमारे नेता अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काम करते रहते हैं। नीतीश कुमार समाज के हर तबके की बात करने वाले नेता हैं। विकास के मामले में कोई उनकी आलोचना नहीं कर सकता।

बीआरएमएसवाई में मदरसा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय और कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित करने पर जोर दे रही है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की उन असीमित शक्तियों पर लगाम लगाना है, जिसके कारण आम मुस्लिम नागरिकों की शिकायतें बढ़ रही हैं।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मामले की हो उच्च स्तरीय जांच: मायावती

लखनऊ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस से आगे निकल गए हैं और केंद्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होता अगर केंद्र अब तक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे देता। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि पहले अदाणी ग्रुप व अब सेबी चीफ सम्बंधी हिण्डनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है तथा आरोप-प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देशहित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अदाणी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि उबाल पर है।

मायावती ने आगे लिखा कि वैसे यह मुद्दा अब सत्ता व विपक्ष के वाद-विवाद से परे केन्द्र की अपनी साख व विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केन्द्र सरकार को अब तक इसकी उच्च-स्तरीय जाँच अर्थात् जेपीसी या जुडिशियल जाँच जरूर बैठा देनी चाहिये थी तो यह बेहतर होता। अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार देर रात जारी अपनी नई रिपोर्ट में कहा था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धबल बुच ने बरमूडा तथा मॉरीशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। उसने कहा कि ये वही कोष हैं जिनका कथित तौर पर विनोद अदाणी ने पैसों की हेराफेरी करने तथा समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था।

विनोद अदाणी, अदाणी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदाणी के बड़े भाई हैं। आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति तथा मार्च, 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले था। ये निवेश "सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से " किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष "निष्क्रिय" हो गए। अदाणी समूह ने भी सेबी प्रमुख के साथ किसी भी तरह के वाणिज्यिक लेन-देन से इनकार किया है। संपत्ति प्रबंधन इकाई 360वन (जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता था) ने अलग से बयान में कहा कि बुच तथा उनके पति धवल बुच का आईपीई-प्लस फंड 1 में निवेश कुल निवेश का 1.5 प्रतिशत से भी कम था और उसने अदाणी समूह के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया था।

अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है भारत: रिजिजू

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि यह दिखाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, किरेन रिजिजू ने कहा कि जब भी पड़ोसी देशों में तनाव या अशांति होती है, तो उन देशों के लोग भारत में शरण लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित देश है।

भाजपा नेता ने कहा कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त समुदाय, हिंदुओं को छोड़कर, अल्पसंख्यक समुदाय हैं। छह मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक, तकनीकी रूप से और परिभाषा के अनुसार हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन किसी भी तरह से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से.... इस देश में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है; एक बहस सामने आई है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। 1959 में जब उत्तरी सीमाओं पर चीन ने हमला किया और तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया, तो तिब्बती लोग भारत आ गए, बर्मा से भी लोग भारत आए; और फिर नेपाल और भूटान से भी शरणार्थी भारत आए।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे लोग भारत आ रहे हैं। श्रीलंका में तनाव के बाद तमिल लोग भी भारत आ गए। हर कोई भारत आता है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश है। मैं भी अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ।

खेल
प्रमुख समाचार

मनु भाकर की नजर भविष्य में कई ओलंपिक पदक जीतने पर

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त हो चुका है और भारतीय खिलाड़ियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने इस बार ओलंपिक में कुल छह पदक अपने नाम किए। इनमें एक रजत और पांच कांस्य शामिल हैं। मनु भाकर ने भारत के लिए दो कांस्य पदक जीते। अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह भविष्य में कई ओलंपिक पदक जीतना चाहेंगी।

स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह दो पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गईं। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और कांस्य पदक दिलाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। मनु एक और कांस्य पदक जीतने के साथ ही एक ही ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गईं।

मनु ने पीटीआई से बात करते हुए अगले ओलंपिक में और पदक जीतने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, हम सभी पदक जीतने के लिये काफी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर भविष्य में दो से अधिक पदक एक ही ओलंपिक में जीत पाती हूं तो यह शानदार होगा। कड़ी मेहनत करके भविष्य में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य है।

उन्होंने ओलंपिक समापन समारोह से लौटने के बाद कहा- मैं भविष्य में भारत के लिये और ओलंपिक पदक जीतना चाहती हूं। मनु समापन समारोह में अनुभवी हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश के साथ भारत की ध्वजवाहक थीं। उन्होंने कहा- यह जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव था । मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं और इसे ताउम्र याद रखूंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 693 अंक टूटा निफ्टी 24,150 के नीचे आया

नईदिल्ली। ब्लू-चिप शेयरों एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाटा मोटर्स और एसबीआई में गिरावट और विदेशी फंड आउटफ्लो के कारण मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स लगभग 700 अंक गिरकर 79,000 के स्तर से नीचे आ गया, जिससे लगातार दूसरे दिन इसका घाटा बढ़ा। इसके अलावा वैश्विक बाजारों के मिले-जुले रुझान भी घरेलू शेयर बाजारों को दिशा देने में विफल रहे। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 692.89 अंक या 0.87 प्रतिशत टूटकर 78,956.03 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 78,889.38 और 79,692.55 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 208.00 अंक या 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,139.00 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,116.50 और 24,359.95 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल 6 शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

इसरो नए भू प्रेक्षण उपग्रह का प्रक्षेपण 16 अगस्त को करेगा

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा है कि उसका नवीनतम भू प्रेक्षण उपग्रह ईओएस-08 अब 16 अगस्त को अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी)-डी3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे पहले अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की थी कि प्रक्षेपण 15 अगस्त को किया जाएगा। इसरो ने प्रक्षेपण एक दिन बाद करने की कोई वजह नहीं बताई है। इसरो ने कहा कि ईओएस-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में एक सूक्ष्म-उपग्रह का डिजाइन और उसका विकास करना, सूक्ष्म-उपग्रह बस के साथ संगत पेलोड उपकरणों का निर्माण करना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को जोड़ना शामिल है।

जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर को

नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक नौ सितंबर को होगी। परिषद ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने आधिकारिक खाते पर लिखा जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक नौ सितंबर 2024 को नई दिल्ली में होगी। केंद्र तथा राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह एक जुलाई 2017 से काम कर रही है। बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर 'स्लैब' को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत उलटा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछली परिषद की बैठक 23 जून को हुई थी, जिसके बाद सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुमंत चौधरी के नेतृत्व में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह कार्य की स्थिति और समिति द्वारा 'कवर' किए गए पहलुओं तथा समिति के समक्ष लंबित कार्यों पर एक प्रस्तुति देगा।

आइनॉक्स विंड को एवररिन्यू से मिला कॉन्ट्रैक्ट

नईदिल्ली। आइनॉक्स विंड को एवररिन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से 51 मेगावाट उपकरण आपूर्ति का ठेका मिला है। कंपनी बयान के अनुसार, आइनॉक्स विंड इसके लिए बहु-वर्षीय परिचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। यह कॉन्ट्रैक्ट आइनॉक्स विंड के नवीनतम तीन मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) से उपकरण आपूर्ति से जुड़ा है। आइनॉक्स विंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैलाश ताराचंदानी ने कहा, " हम एवररिन्यू से 51 मेगावाट का ठेका पाकर खुश हैं। एवररिन्यू एक बड़ा ग्राहक है जिसके साथ हम भविष्य में पारस्परिक रूप से लाभदायक साझेदारी करने का लक्ष्य रखते हैं।" कंपनी ने हालांकि ठेके से जुड़ी वित्तीय जानकारी साझा नहीं की। यह परियोजना तमिलनाडु में क्रियान्वित की जाएगी।

खेल प्रदर्शन में सुधार की पूरी गुंजाइश

मनोज चतुर्वेदी

भारत का पेरिस ओलिंपिक का अभियान कुछ खुशियों और तमाम सुधार की गुंजाइशों के साथ खत्म हो गया। भारत ने टोक्यो ओलिंपिक के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर एक रजत सहित छह पदक जीते। इस प्रदर्शन से वह पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। इसमें महिला पहलवान विनेश फोगाट का एक रजत पदक और शामिल हो सकता है। विनेश को यदि खेल पंचाट न्यायालय पदक दिला देता है, तो भारत 71वें स्थान से खिसककर 68वें स्थान तक आ सकता है।

भारत ने पिछले ओलिंपिक के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन ही नहीं किया है, बल्कि इस बार पदक तालिका में पाकिस्तान के 62वें स्थान से पीछे है। पाकिस्तान के जेवेलिन थ्रोअर नदीम अशरफ ने नीरज चोपड़ा को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश को भारत से आगे निकाला है। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही पदक जीता है, पर पदक तालिका में स्थानों का निर्धारण स्वर्ण पदकों के हिसाब से होता है। भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए बिना स्वर्ण के छह पदक जीतना बहुत खुशियां नहीं देता है। हमें और कुछ नहीं, तो टॉप 20 देशों में तो शामिल रहना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे खिलाड़ियों को चार स्वर्ण पदक जीतना होगा। तब हम इसे सम्मानजनक प्रदर्शन कह सकते हैं।

भारत के लिए दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर, रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, स्वप्निल कुसाले, पहलवान अमन सेहरावत, सरबजोत सिंह और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। पर हम शायद खिलाड़ियों की मानसिक शक्ति पर ज्यादा

काम नहीं करने की वजह से इस स्थिति में पहुंचे हैं। छह खिलाड़ी ऐसे थे, जो पदक के करीब पहुंचकर भी नहीं जीत सके। ये खिलाड़ी थे- निशानेबाज अर्जुन बबुता, तीरंदाज बोम्मादेवरा धीरज और अंकिता भकत की जोड़ी, महेश्वरी चौहान और अनंतजीत की जोड़ी, शटलर लक्ष्य सेन और मनु की तीसरी स्पर्धा। ये पदक आ जाते, तो भारत के पदकों की संख्या दहाई अंक में पहुंच जाती।

भारत के लिए छह खिलाड़ियों और टीमों के पदक जीतने, आधा दर्जन पदक हाथ से खिसकने के अलावा 15 स्पर्धाओं में भारत ने क्वार्टर फाइनल तक चुनौती पेश की। इससे यह तो साफ है कि भारत बढ़ तो सही दिशा में रहा है, जरूरत सिर्फ इन प्रयासों को थोड़ी और गति देने की है ताकि भारत दिग्गजों के साथ खड़ा नजर आने लगे। अब हमारे खिलाड़ी सुविधाओं का रोना नहीं रो सकते हैं। उन्हें हर वह सुविधा उपलब्ध करायी गयी, जिसकी जरूरत थी। भारत सरकार ने खिलाड़ियों की तैयारियों पर 470 करोड़ रुपये खर्च किये। अमेरिका जैसे कुछ देशों में हुए खर्च के मुकाबले यह कम हो, पर इतना जरूर है कि इतने पदक लाये जा सकें, जिससे देश खुशी से झूम उठे।

हम एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी और वेटलिफ्टिंग में आशा के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे। हॉकी में भारत ने भले ही कांस्य पदक जीता है, पर यह भारतवासियों के लिए सोने के तमगे से कम कतई नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ओलिंपिक हॉकी में भारत का सालों तक दबदबा रहा है। पर 1980 के मास्को ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हॉकी के स्तर में निरंतर गिरावट आने से 2008 के बीजिंग ओलिंपिक तक यह रसातल में पहुंच गयी थी। पर टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। अब भारत ने लगातार दूसरे ओलिंपिक में पदक जीतकर यह तो जता दिया है कि वह अब बड़ी टीमों में शुमार हो गयी है। सच तो यह है कि भारतीय टीम ने यदि सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ गलती नहीं की होती, तो इस बार पदक का रंग जरूर बदल जाता। भारत को अब जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, उस पर इतराने के बजाय, 2028 के लॉस एंजिल्स ओलिंपिक के लिए अभी से योजना बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ में निर्यात-उद्यमिता विकास के लिए होगी दो राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता (आईआईएफटी) के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य से निर्यात गतिविधियों में वृद्धि होगी। इससे छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाने वाले प्रशिक्षण केंद्र से प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण मिलेगा। यह केंद्र युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और उसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करेगा।

इन दोनों राष्ट्रीय स्तर के केंद्रों की स्थापना से छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति को और भी गति मिलेगी। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित किया गया, जहां एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और इन केंद्रों की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।

विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश भर में संगोष्ठी : अनुराग

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विभाजन विभीषिका दिवस आयोजन के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि भाजपा के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विभाजन विभीषिका दिवस का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें विभाजन विभीषिका के दौरान की घटनाओं का चित्रण कर एलईडी के माध्यम से विभाजन विभीषिका के दृश्य दिखाए जाएंगे। विभाजन विभीषिका के दौरान लाहौर से अमृतसर पहुँची एक ट्रेन में हुई विभीषिका भी दिखाई जाएगी। सिंहदेव ने कहा कि प्रदेशभर में इस मौके पर संगोष्ठियाँ भी रखी जाएंगी और देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातनाओं और वेदना का स्मरण कराया जाएगा।

सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभाजन विभीषिका स्मृति के दृष्टिगत संगोष्ठी का आयोजन भी होगा। राजधानी के मेडिकल कॉलेज सभागार में होने वाली संगोष्ठी में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश होंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विचारक एवं फिल्म कलाकार मुकेश खन्ना, विधायक व पूर्व मंत्री राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, और विधायक मोतीलाल साहू भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संगोष्ठी-परिचर्चा के उपरांत एक मौन जुलूस हाथ में तिरंगा लेकर मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर तेलीबांधा मरीन ड्राइव में समाप्त होगा। यहां मुख्यमंत्री साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश एवं विचारक-कलाकार खन्ना के हाथों एक 10 फीट ऊँची मशाल प्रज्वलित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सुकमा में संगोष्ठी के मुख्य वक्ता होंगे। उनके साथ सुधीर पांडेय भी रहेंगे। इसी प्रकार रायपुर ग्रामीण में सांसद संतोष पांडेय व प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, बलौदाबाजार में प्रदेश के मंत्री दयालदास बघेल व यशवंत जैन, गरियाबंद में प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा, महासमुंद में विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, धमतरी में सांसद विजय बघेल व आलोक ठाकुर, भिलाई में प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंग सवन्नी, दुर्ग में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी व राजा पांडेय, बेमेतरा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व पूर्व विधायक रजनीश सिंह, बालोद में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, राजनांदगाँव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल व विधायक मोतीलाल साहू, मोहला-मानपुर-चौकी में प्रदेश महामंत्री रामजी भारती व विक्रांत सिंह, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा व प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा, कवर्धा में जगन्नाथ पाणिग्रही, कांकेर में वन मंत्री केदार कश्यप, कोंडागाँव में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी व अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय, नारायणपुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, टेकेश्वर जैन व संजय पांडेय, बस्तर में उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा व निरंजन सिन्हा, दंतेवाड़ा में श्रीनिवास राव मद्दी व अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, बीजापुर में डॉ. सुभाऊ कश्यप व शिवनारायण पांडेय कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी अनुराग अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल, प्रदेश प्रवक्ता अमरजीत छाबड़ा, सोशल मीडिया सह संयोजक मितुल कोठारी, विभाजन विभीषिका दिवस आयोजन की सदस्य विश्वदिनी पांडेय और जिला मीडिया सह प्रभारी वंदना राठौड़ की उपस्थिति रही।

बृजमोहन ने निकाली तिरंगा यात्रा

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, यात्रा का मकसद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे का प्रचार-प्रसार करना है। साथ ही लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना और स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाना था। इस तरह की यात्रा से लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है और यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करता है। तिरंगा न केवल हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह हमारी आज़ादी, संप्रभुता, और देशभक्ति की भावना का प्रतीक भी है। जब हर घर पर तिरंगा लहराएगा, तो यह हमारे देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देगा।

भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा क भाजपा की सरकार बनते ही एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। राजनांदगांव पुलिस ने जिन्हें तेंदूपत्ता ठेकेदार से नक्सलियों के लेवी वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है उसी ठेकेदार सुधीर कुमार माणिक ने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के रिश्तेदार पेखन गागड़ा के खाता क्रमांक 11521261288 में लगभग 91 लाख डाला था। जिसे विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेसवार्ता कर 29/03/2023 को आरोप लगाया था। पुलिस भाजपा नेता पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को बचाने लेवी वसूलीकर्ता पेखन गागड़ा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। भाजपा नेताओं का संबंध नक्सलियों से है। भाजपा सरकार अपनी काली करतूत छिपाने कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि इन्होंने ठेकेदारों से दबाव डालकर वसूली की ताकि नक्सलियों तक राशि पहुंचाई जा सके. जिन ठेकेदारों से वसूली के आरोप हैं उनमें एक नाम सुधीर माणिक का भी है. सुधीर माणिक वही ठेकेदार हैं जिनसे पेखन गागड़ा के खाते में लाखों रुपए डलवाये हैं. 29 मार्च, 2023 को बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी जी ने प्रेसवार्ता लेकर सबूत सहित आरोप लगाए थे कि पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लवकुमार रायडू ने दबाव डालकर ठेकेदार से 91 लाख रुपए अपने रिश्तेदार पेखन गागड़ा के खाते में जमा करवाए. पेखन गागड़ा भैरमगढ़ में रहते हैं. नक्सल मामले में किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए. न अभी गिरफ्तार किए गए इन पांच लोगों को और न पेखन गागड़ा को. यह गंभीर मामला है. इसमें सरकार और पुलिस को मेरा तेरा नहीं देखना चाहिए. एक जैसे मामले हैं तो एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए. अगर ये पांच लोग नक्सलियों के लिए वसूली कर रहे थे तो पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के रिश्तेदार पेखन गागड़ा को भी इन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

इंदिरा गांधी कृषि विवि ने लहराया सफलता का परचम, एनआईआरएफ रैंकिंग में मिला 39वां स्थान

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर कामयाबी का परचम फहराते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) द्वारा जारी टॉप 40 संस्थानों में जगह बनाई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य से एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाला एक मात्र विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है कि मध्यप्रदेश एवं राजस्थान जैसे बड़े एवं विकसित राज्यों से किसी भी कृषि विश्वविद्यालय को एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में जगह नहीं मिली है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने इस उपलब्धि के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों, प्राध्यापकों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के 145 कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों में 39वां स्थान हासिल करना गर्व का विषय है। डॉ. चंदेल ने बताया कि विश्वविद्यालय को यह रैंकिंग पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय प्रयासों तथा अधोसंरचना विकास के लिए किये जा रहे कार्यों को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालय की एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में और भी सुधार होगा तथा

जल्द ही हम देश के टॉप 25 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग हेतु निर्धारित मापदण्डों जैसे अधोसंरचना विकास (महाविद्यालय भवन, छात्रावास, लाईब्रेरी, सभागृह आदि) छात्र सुविधाएं, छात्र शिक्षक अनुपात, अनुसंधान कार्य, शोध पत्र प्रकाशन, पेटेन्ट, नवाचार, उद्यमिता विकास आदि सभी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय कार्य किया है जिसका लाभ आने वाले वर्षों में जारी रैंकिंग में मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का कार्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 28 शासकीय कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण हो चुका है अथवा प्रगति पर है। सभी महाविद्यालयों में छात्रावास, लाइब्रेरी, सभागृह उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। 477 नवीन प्रौद्योगिकी, उत्पादों एवं पौध किस्मों के पेटेन्ट प्राप्त हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

पुलों पर बैरियर, रिफ्लेक्टर-साइनबोर्ड लगाने के निर्देश

रायपुर। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने नदियों पर बने पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य कराने को कहा है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता ने वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से जान-माल की सुरक्षा और सुरक्षित यातायात के लिए सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं एवं संभागीय कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को हर 15 दिनों में अनुविभागीय अधिकारियों और कार्यपालन अभियंताओं के साथ इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी ने परिपत्र में निर्देशित किया है कि ऐसे सभी स्थानों और मार्गों जिनमें वर्षा ऋतु में आम जनता के लिए समस्या की स्थिति उत्पन्न होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बारिश के दिनों में अतिवृष्टि से मार्गों पर विद्यमान नदी-नालों पर बाढ़ एवं कई स्थानों में सड़क डूबने जैसी स्थिति निर्मित होती है। इन स्थितियों में जान एवं माल की सुरक्षा तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षित कार्य के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

शिक्षकों के पद को खत्म करने की साजिश

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम से प्रदेश के 4077 सरकारी स्कूलों और 12000 शिक्षकों के पद को खत्म करने की साजिश कर रही है। 4077 स्कूलों को बंद कर यहां के शिक्षकों को उन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। इन स्कूलों के बंद होने से यहां काम कर रहे 4 हजार रसोईया, 4 हजार स्वीपर और महिला स्व सहायता समूह जो मध्यान्ह भोजन बनाती है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे 20 हजार प्राइमरी और मिडिल स्कूल जहां शिक्षकों के रिक्त पद है। वहां अब शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी मतलब साफ है। प्रदेश में 32000 शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 57000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था और बेरोजगार युवाओं से वोट लिया था। भाजपा एक ओर सरकारी स्कूल को बंद कर रही है शिक्षकों के पद को खत्म कर रही है दूसरी ओर युवाओं से भी वादाखिलाफी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में युक्तियुक्तकरण के नाम से 3500 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया था।

भाजपा का तिरंगा अभियान केवल दिखावे के लिये

रायपुर। भाजपा का तिरंगा अभियान केवल दिखावे के लिये है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के लिये आन बान शान है, लेकिन भाजपा के लिये यह राजनैतिक विषय वस्तु है। भाजपा बताये आजादी के बाद 52 सालों तक संघ के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था? आजादी के बाद दशकों तक भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस ने क्यों राष्ट्रध्वज को स्वीकार नहीं किया था? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा भाजपाई आत्म अवलोकन करें कि उनके पूर्वजों ने क्यों तिरंगे को अपमानित किया था। आज भी संघ के शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता? देशवासी तो गर्व से अपने घरों में तिरंगा फहराते है, संघ की शाखाओं में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने हो 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाने लगा। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर देश भक्ति का जलसा निकालने की नौटंकी करने वालों के पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के पैरोकार की भूमिका में खड़े थे।

प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व के लिए मैं तैयार हूँ- सिंहदेव

रायपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए है। आज वह राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस की फैक्ट फाईंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार पर चर्चा हुई और मोइली कमेटी की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के संगठन में बदलाव किए जाएंगे। सिंहदेव ने संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि इसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारा फोकस सामूहिकता के साथ काम करने पर है और पार्टी द्वारा दी गई किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। अगर प्रदेश में नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसके लिए भी तैयार हूं। दिल्ली में कांग्रेस की फैक्ट फाईंडिंग कमेटी की बैठक पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोइली कमेटी की बैठक में चुनावों में हार के कारणों पर वन टू वन चर्चा हुई है। यह पहली बार है कि कांग्रेस इस तरह से रिपोर्ट तैयार कर रही है, और मोइली कमेटी की रिपोर्ट से पार्टी और मजबूती से काम करेगी। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने पर भी चर्चा हुई। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि इससे व्यवस्था बिगड़ेगी।

छत्तीसगढ़ में हत्या के आरोपी को मृत्युदंडः

बिलासपुर। चरित्र शंका पर पत्नी समेत तीन बच्चों की हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री में रहने वाले उमेंद्र केंवट की शादी 2017 में सुक्रिता केवट से हुई थी। दोनों के तीन बच्चे पुत्री खुशी, लिसा और पुत्र पवन थे, जिनकी उम्र लगभग 5 वर्ष, 3 वर्ष और 18 माह थी। आरोपी उमेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और आए दिन मारपीट झगड़ा भी बात करता था। इसी बात को लेकर आरोपी ने 1 जनवरी 2024 की रात अपनी पत्नी एवं तीनों बच्चों का बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी. 2 जनवरी को प्रार्थी सुमन केवट को सुबह 3:30 बजे उसके मोबाइल फोन से पता चला कि उसके बहनोई उमेंद्र केवट ने चरित्र शंका की बात को लेकर सुकृता केवट और उनके बच्चे खुशी केवट, दिशा केवट और पवन केवट की हत्या कर दी है. उन्होंने अपने घर परिवार और गांव वालों के साथ आरोपी के घर जाकर देखा तो गांव वालों की भीड़ थी. घर के अंदर जाकर देखा तो आरोपी के घर के पीछे बाड़ी में शौचालय के पीछे बहन सुक्रिता केवट औंधे मुंह गिरी पड़ी थी, जिसके मुंह और गले पर चोट के निशान थे. घर में प्रार्थी सुमन के जीजा एवं दीदी अपने बच्चों के साथ रहते थे. वहां अंदर लगे बेड के किनारे तरफ भांजी खुशी बुरी हालत में और लिसा केवट बाएं तरफ करवट लेते हुए और बेड के बीच में भांजा पवन चित हालत में मृत पड़े हुए थे.

मुख्यमंत्री राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह में हुए शामिल

क्षत्रिय समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा हैः मुख्यमंत्री साय

रायपुर। विष्णुदेव साय राठौर समाज द्वारा राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की 386 वीं जयंती के अवसर पर आज गुरुकुल खेल मैदान गौरेला में आयोजित समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पहली बार मुख्यमंत्री के नाते राठौर समाज द्वारा आयोजित गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने पर समाज को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत माता और राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की जयकारों के साथ अपना उद्बोधन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षत्रिय समाज का देश के इतिहास में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। दुर्गादास राठौर मारवाड़ के वे वीर सपूत थे जहां आज भी लोग कहते है कि बेटा हो तो दुर्गादास जैसा। दर्गादास की वीरता पर अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है, मैं ऐसे वीर योद्धा को प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री ने वीरता के प्रतीक के रूप में केसरिया ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री साय ने राठौर समाज की मांग पर कलेक्ट्रेट के सामने जिला अस्पताल परिसर में 60 डिसमिल जमीन जिस पर राठौर समाज का कब्जा है, मकान बना है और बाउंड्रीवाल युक्त है, को राठौर समाज के नाम पर करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही साहू समाज के सांस्कृतिक भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होने कहा कि जिले वासियों की मांग पर नगर पंचायत गौरेला एवं नगर पंचायत पेंड्रा को नगर पालिका परिषद बनाने अधिसूचना जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर घर तिरंगा फहराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर लगाने लोगों से आग्रह किया। उन्होने प्रणव कुमार मरपच्ची को विधायक चुनने और तोखन साहू को सांसद चुनने पर जिले वासियों को बधाई देते हुए कहा कि हम चुनाव पूर्व किए गए घोषणाओं-महतारी वंदन योजना, पीएम आवास, राम लला दर्शन, तेंदूपत्ता दर बढ़ाने सहित सभी घोषणाओं को सायं-सायं पूरा कर रहे है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्रधान मंत्री श्री मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यो कि सराहना करते हुए देश और समाज को आगे बढ़ाने में राठौर समाज को संगठित होकर कार्य करने पर उनके योगदान की सराहना की उन्होंने राज्य मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जयसवाल ने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की वीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन राठौर समाज का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण हिन्दू समाज का आयोजन है।

श्रम मंत्री ने रक्षाबंधन पर श्रमिकों को दिया 14.47 करोड़ का तोहफा

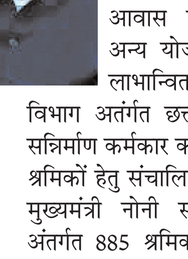

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक सौगात दी है। यह राशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्री ने भी विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपए की स्वीकृति प्रदान की। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, आवास सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किए जाता है। श्रम विभाग अतंर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे-मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 885 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.